राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHI/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 331 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, बुधवार, 09 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

पीएम से मराठा आरक्षण, जीएसटी संग्रहण पर हुई बातः उद्धव ठाकरे

नई दिल्ली । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मराठा आरक्षण, चक्रवात ताउते पर राहत उपायों के लिए वित्तीय सहायता समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की. मुख्यमंत्री के साथ राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण भी प्रधानमंत्री से मिले थे. मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने बताया कि कुल 12 मुद्दों पर पीएम के साथ चर्चा हुई और उन्होंने इन पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है. बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत सकारात्मक रही. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री से यह अधिकृत भेंट थी, जिसके कारण सबको पता हैं. आरक्षण, मेट्रो कारशेड, जीएसटी के लेन-देन पर हमारी बातचीत हुई. खास कर मराठा और ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हुई. पदोन्नति पर

आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर हमने अपना मत रखा. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ 30 मिनट तक व्यक्तिगत चर्चा भी हुई.

उन्होंने कहा कि सत्ता में साथ नहीं होने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते. बालासाहेब ठाकरे के समय से यह नाता है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर जो नई याचिका दाखिल की है, उस पर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा, पीएम से मांग की है कि कोविड महामारी में जीएसटी का पैसा राज्य को जल्द से जल्द मिले. साथ ही महाराष्ट्र में जो ताउते तूफान आया था, उसको लेकर केंद्र सरकार से सहायता मांगी है.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि 5 साल में चार बार चक्रवातीय तूफान आए हैं, समुद्र किनारों पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे नुकसान कम हो. उन्होंने कहा कि तूफान प्रभावितों के लिए मदद की शर्तों और मापदंडों पर भी बातचीत हुई. उन्होंने कहा, ÷मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने, किसानों के लिए फसल बीमा को लेकर, कंजूरमार्ग में मेट्रो कारशेड के लिए जगह, 50 फीसदी आरक्षण सीमा को शिथिल करने जैसे मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई.

एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने से संबंधित 2018 का आरक्षण कानून रद्द कर दिया था. इसके बाद पिछले महीने सीएम उद्धव ठाकरे ने मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में जोड़ने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा था, ताकि वे आरक्षण का लाभ उठा सकें.

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा लांघने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी, जिसका निर्धारण 1992 के मंडल फैसले में किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई को आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के तहत दिये जाने वाले आरक्षण का लाभ मराठा समुदाय को देने की घोषणा की थी. सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि मराठा समुदाय 10 फीसदी EWS आरक्षण का लाभ ले सकता है.

एक नज़र...

वैष्णो देवी मंदिर में लगी आग, यात्रा यथावत जारी

जम्मू, (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी भवन में मंगलवार को आग लगने से कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है और तीर्थयात्रा भी सुचारू रूप से जारी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने बताया कि भवन में दोपहर बाद करीब चार बजे आग लगी। उन्होंने बताया कि दमकल वाहनों की मदद से करीब 4.25 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया और इस दौरान काई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है और यात्रा में भी कोई बाधा नहीं आई है।

चार डॉक्टरों पर गैंगरेप का आरोप, युवती की मौत

प्रयागराज, (एजेंसी)। एसआरएन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों पर दुष्कर्म के आरोप मामले से संबंधित युवती की इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। 21 मई को ऑपरेशन के बाद से ही वह एसआरएन अस्पताल के आईसीयू में एडमिट थी। इस मामले में मृतका के भाई की तहरीर पर एसआरएन अस्पताल के चार चिकित्सा स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक जो पुलिस सीएमओ की जांच रिपोर्ट का हवाला देकर कार्रवाई से कर रही थी, किशोरी की मौत के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई।

पंजाबी सिंगर जेजी बी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा पिछले साल दिसंबर में जारी आंदोलन अभी तक जारी है। कृषकों को कई बड़ी हस्तियों का समर्थन मिल रहा है। उनमें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार भी शामिल है। किसान आंदोलन का गायक जैजी बी सपोर्ट कर रहे हैं। वह लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में जैजी बी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। उनके ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि वह देश के बाहर अपना अकाउंट चला सकते हैं। सिंगर के ट्विटर खाते को भारत में बैन करने पर ट्विटर इंडिया ने बयान भी जारी किया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को शख्स ने मारा चांटा

पेरिस, (एजेंसी)। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को देश के दक्षिण हिस्से के दौरे के दौरान एक व्यक्ति ने चांटा मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मैक्रों दक्षिण-पूर्वी फ्रांस के ड्रोम इलाके के एक दौरे पर गए थे और वहां मौजूद भीड़ से जब वो हाथ मिलाने गए, तो एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। मैकों की सुरक्षा टीम ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया और राष्ट्रपति को वहां से दूर ले गए। इस घटना के संबंध में दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। वे होटल मालिकों व छात्रों से मिले और कोविड महामारी के बाद जिंदगी के पटरी पर लौटने को लेकर चर्चा की।

गांवों में कचरा प्रबंधन के लिए 40,700 करोड़ आवंटित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के तहत सूखा एवं गीला कचरा प्रबंधन के तहत दो लाख से अधिक गांवों की मदद के लिए 40,700 करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है। केंद्र करीब 14,000 करोड़ खर्च करेगा, जबकि राज्य 8,300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तथा शेष राशि अन्य स्रोतों से आएगी। जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया ने एसडब्ल्यूबी (जी) की प्रगति की समीक्षा की। मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एमबीएम-जी की राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजना को मंजूरी दी।

वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी, टीके की बर्बादी पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कम मिलेंगी डोज

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई वैक्सीन गाइडलाइन को मंजूरी दी है. इसके तहत आगामी 21 जून से वैक्सीन का कैसे वितरण होगा और किस राज्य को किस आधार पर कितनी वैक्सीन मिलेगी इसका ऐलान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन में कर दिया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगायी जाएगी. सबसे पहले हेल्थकेयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 45 से ऊपर की उम्र के लोग, दूसरी डोज जिन लोगों की लंबित हो, फिर आखिर में 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी. हालांकि देश में अधिकतर हेल्थकेयर वर्करों का वैक्सीनेशन हो चुका है. बावजूद इसके अभी भी जो कोई बाकी है या रह गए हैं, उन्हें वैक्सीन पहले देनी होगी.

वैक्सीन वितरण राज्य तय करें- केन्द्र सरकार की नई गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि वैक्सीन के वितरण कैसे हो. इसके लिए स्थानीय राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गयी है. किसे पहले वैक्सीन लगवाना है, इसे लेकर राज्य सरकार अपनी प्राथमिकता तय कर सकती है. यदि राज्य सरकार को लगता है कि पहले 45 प्लस को वैक्सीन देना ज्यादा जरुरी है तो पहले उन्हें वैक्सीन मुहैया कर सकती हैं.

किस राज्य को कितनी वैक्सीन- केन्द्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राज्य को वहां की जनसंख्या और संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी. इसमें यह भी तय कर दिया गया है कि किसी राज्य में वैक्सीनेशन की क्या रफ्तार है, इसे ध्यान में रखकर भी वैक्सीन दी जाएगी. यदि किसी राज्य में वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीन की बर्बादी ज्यादा हुई है तो ऐसे में आने वाले दिनों मे उसे कम वैक्सीन भी मिल सकती है.

केन्द्र सराकर ने राज्यों से यह भी स्पष्ट कहा है कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलने वाली है, इसकी जानकारी समय रहते दी जाएगी. इससे वैक्सीन सेंटर बनाने से लेकर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी.

इस गाइडलाइन में यह भी तय किया गया है कि वैक्सीन बनाने वाली कम्पनियां जितनी वैक्सीन बनाएंगी उसकी 25 प्रतिशत वैक्सीन वह प्राइवेट अस्पतालों को देने के लिए स्वतंत्र है. प्राइवेट अस्पताल इस बारे में सीधे वैक्सीन कम्पनी से बात करेंगे और वैक्सीन उत्पादक कम्पनी राज्य में स्थित अस्पताल की स्थिति को देखते हुए वैक्सीन मुहैया कराएंगी.

चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने वालों के लिए हो दो साल की सजा, सुशील चंद्रा ने कानून मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली । लंबित चुनाव सुधारों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लंबित चुनाव सुधार प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा मैंने इन प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखा है और उम्मीद है कि मंत्रालय इन पर जल्द विचार करेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह पत्र पिछले महीने पत्र भेजा था। जिसमें उन्होंने चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने वालों के लिए कारावास की अवधि मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर दो साल करने का प्रमुख चुनाव सुधार प्रस्ताव रखा है।

इसके साथ दो साल की जेल की सजा वाले उम्मीदवार को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगाए जाने की मांग की गई है। कानून मंत्री को लिखे पत्र में सुशील चंद्रा ने चुनाव प्रचार के अंतिम और मतदान वाले दिन समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव किया है ताकि मतदाता प्रभावित न हों और स्वतंत्र दिमाग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अभी तक, केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मतदान के खत्म होने से 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार सामग्री दिखाने से रोक दिया गया है। लेकिन समिति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के दायरे में अब प्रिंट मीडिया को भी लाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सुधारों में एक और प्रस्ताव मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का है।

मरीजों से मॉकड्रिल करने वाला आगरा का पारस हॉस्पिटल सील

22 मरीजों की हो गई थी मौत

आगरा, (एजेंसी)। पारस हॉस्पिटल में मरीजों के साथ मॉकड्रिल के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मॉकड्रिल करने वाले पारस हॉस्पिटल को सील किया गया है। यहां भर्ती मरीजों को शिफ्ट किया गया। अस्पताल के संचालक पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह ने पारस अस्पताल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सुबह से ही पारस हॉस्पिटल के बाहर लोगों का हंगामा होता रहा। इसे देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई।

योगी ने दिए जांच के आदेश: 28 अप्रैल को पारस अस्पताल में पांच मिनट के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति रोकने की मॉकड्रिल से 22 लोगों की मौत हो गई, अब इस मामले ने तूल पकड़ा जब अस्पताल संचालक का एक वीडियो वायरल सामने आया। वायरल वीडियो में ऑक्सीजन संकट में मॉक ड्रिल से पांच मिनट में 22 मरीजों की मौत की बात सामने आने के बाद से खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पारस अस्पताल के संचालक डा अरिंजय जैन के वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए गए हैं। वायरल वीडियो में डॉ. जैन की आक्सीजन की कमी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि माक ड्रिल के जरिये यह पता करते है कि पांच मिनट के लिए आक्सीजन आपूर्ति बाधित करने से कितने मरीजों की जान पर संकट आ सकता है। इस वायरल वीडियो पर गंभीर रूख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं।

एफसीआई कर्मी के खिलाफ केस दर्ज, सीबीआई के छापे

भोपाल, (ब्यूरो)। सीबीआई ने एफसीआई के भोपाल मंडल कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी किशोर मीना के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में अपराध दर्ज किया गया। इस मामले में सीबीआई ने मंगलवार को मप्र और महाराष्ट्र के 13 जगह छापा मारा।

मप्र, महाराष्ट्र के 13 ठिकानों पर छापे

प्रदेश में जबलपुर व नरसिंहपुर समेत भोपाल, विदिशा, खंडवा, झाबुआ में एक साथ कार्रवाई की। जबलपुर व नरसिंहपुर में चार ट्रांसपोर्टरों के यहां छापे मारे गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक हर्ष इनायका के खाते में इन ट्रांसपोर्टरों द्वारा पैसों का भुगतान किया गया है। एफसीआई रिश्वत मामले में सीबीआई भोपाल से एक इंस्पेक्टर जबलपुर पहुंचे थे। स्थानीय सीबीआई की टीम के साथ बल्देवबाग स्थित बालाजी, नर्मदा, तिरुपति और नरसिंहपुर स्थित नरेंद्र राजपूत ट्रेवल्स नाम के ट्रांसपोर्टरों के यहां टीम पहुंची थी। यहां से टीम ने उनके बैंक डिटेल्स और एफसीआई के डिविजनल मैनेजर के खाते में रकम जमा करने के संबंध में पूछताछ की है।

जबलपुर सीबीआई एसपी पीके पांडे ने बताया, भोपाल से आए इंस्पेक्टर ने सर्चिंग में मदद के लिए टीम मांगी थी। कार्रवाई भोपाल सीबीआई की है। जांच की जद में आने वाले सभी लोग ठेके पर काम करने वाले कॉन्ट्रेक्टर और कुछ परिवहन से जुड़े लोग हैं। सीबीआई ने इसके अलावा भोपाल, विदिशा, खंडवा, झाबुआ, और महाराष्ट्र के नांदेड व जलगांव में भी छापामार कार्रवाई की है।

ई-फाइलिंग पोर्टल में खामियों से इंफोसिस और नंदन नीलेकणि पर भड़कीं वित्त मंत्री

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल को सोमवार रात 8.45 बजे यह कहते हुए लॉन्च किया कि इसे पहले से बेहतर बनाया गया है। इससे टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग में आसानी होगी। हालांकि, हुआ इसका उलटा और नई वेबसाइट में खामियों की शिकायतें आने लगीं। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि पर भड़क गईं। वित्त मंत्री सीतारमण ने इंफोसिस व नीलेकणि को टैग करते हुए ट्वीट किया कि करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उम्मीद है कि इंफोसिस व नंदन नीलेकणि सेवा की गुणवत्ता के मामले में टैक्सपेयर्स को निराश नहीं करेंगे। नया पोर्टल सोमवार सुबह ही लांच होना था, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण इसे रात 8.45 बजे लॉच किया गया। इसके बाद भी इसमें गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार आ रही हैं।

दुनियाभर की कई वेबसाइट डाउन

यूके सरकार की साइट भी पड़ी ठप

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ग्लोबल इंटरनेट डाउन होने की वजह से दुनिया की कई बड़ी वेबसाइट्स के क्रैश होने की खबर है। रेडडिट, स्पॉटिफाई, ट्वीच, स्टेक ओवरफ्लो, गिटहब, गॉव.यूके, द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, फाइनेंशियल टाइम्स सहित कई वेबसाइट ठप पड़ गई हैं। आमतौर पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कारण इस तरह का आउटेज होता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) के ग्लोबली ठप होने की वजह से दिक्कत आ रही है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि लोकप्रिय सीडीएन प्रोवाइडर फास्टली में दिक्कत के कारण ऐसा हुआ है। फास्टली ने भी अपनी साइट पर इस आउटेज की पुष्टि की है। सीडीएन को इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर का नींव माना जाता है। सीडीएन प्रोवाइडर कंपनियां तमाम सर्वर के ग्लोबल नेटवर्क के जरिए वेब सर्विस को बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं।

राजनाथ सिंह ने भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए स्वीडन रक्षा प्रमुखों को आमंत्रित किया

नई दिल्ली । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को प्रमुख स्वीडन रक्षा कंपनियों को भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य उपकरणों और प्लेटफार्मों के उत्पादन के निवेश हेतु भारत एक आकर्षक जगह है। भारत-स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग पर एक सम्मेलन के दौरान संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने रक्षा उद्योगों को न केवल भारतीय आवश्यकताओं को पूरा करने बल्कि वैश्विक मांगों को पूरा करने में मदद करने के लिए सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है।

रक्षा मंत्री ने स्वचालित मार्ग से 74 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में सरकारी मार्ग से 100 फीसद तक की अनुमति देने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्रित एफडीआई नीति भारतीय उद्योगों को विशिष्ट और सिद्ध सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्वीडिश उद्योगों के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाएगी।

मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड- रक्षा मंत्री बोले, स्वीडन और भारतीय रक्षा उद्योगों के लिए सह-उत्पादन और सह-विकास की भारी गुंजाइश है। भारतीय उद्योग स्वीडिश उद्योगों को भी कलपुर्जो की आपूर्ति कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन आत्मनिर्भर भारत लागत प्रभावी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन के लिए हैं और इसका मूल आदर्श - मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड है। अपने संबोधन में, रक्षा मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारत में विश्व स्तरीय सार्वजनिक और निजी जहाज निर्माण कंपनियों के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एक मजबूत जहाज निर्माण उद्योग है। उन्होंने कहा कि भारतीय शिपयार्ड द्वारा निर्मित जहाज वैश्विक मानकों के हैं और अत्यधिक लागत प्रभावी हैं।

उन्होंने कहा, मैं इस अवसर पर स्वीडिश फर्मों को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के समर्पित रक्षा गलियारों में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां वे राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे अनूठे प्रोत्साहनों और भारत में अत्यधिक कुशल कार्यबल की उपलब्धता से बहुत लाभ उठा सकते हैं।

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू नई दिल्ली में सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बोलते हुए ।

कोरोना की जंग — 5वीं की छात्रा ने सीजेआई को लिखा दिल को छूने वाला खत

अहम हस्तक्षेप के लिए अदा किया शुक्रिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केरल में पढ़ने वाली 5वीं क्लास की एक छात्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमणा को खत लिखा है। छात्रा ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में अदालत के प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप और इस संक्रमण काल में जिंदगियां बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है।

थ्रिशूर केंद्रीय विद्यालय की छात्रा लिडविना जोसेफ ने अपने खत के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई चित्र और अन्य तस्वीरें भी खुद से ड्राइंग कर भेजी है।

इस छात्रा ने खत में लिखा है कि कोरोना की वजह से दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों में हो रही मौतों से मैं काफी चिंतित थी। अखबार पढने के बाद मझे समझ आया कि

माननीय अदालत ने कोरोना महामारी से लड़ने और इस दौरान आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मजबूती से हस्तक्षेप किया है। मैं खुश हूं और इस बात को लेकर काफी गर्व महसूस कर रही हूं कि माननीय अदालत ने ऑक्सीजन की सप्लाई करने का निर्देश दिया जिससे कई जिंदगियां बच गईं।

सीजेआई ने भी तहे दिल से कहा शुक्रिया

केरल की पांचवीं कक्षा की एक छात्रा द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की सराहना वाले पत्र की भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने प्रशंसा की है। खास बात यह भी है कि छात्रा के खत पर देश के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। एन वी रमणा ने छात्रा को शुभकामनाएं दीं और खत के साथ छात्रा ने काम करते हुए एक जज की जो ड्राइंग उन्हें भेजी थी उसके लिए भी छात्रा का तहे दिल से शुक्रिया कहा। मुख्य न्यायाधीश ने लिखा कि मुझे आपका प्यारा खत मिला जिसमें दिल को छू लेने वाली तस्वीरें भी थीं। मैं इस बात से काफी प्रभावित हूं कि आप देश में हो रही घटनाओं को लेकर इतनी सजग रहती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक सजग और जिम्मेदार नागरिक बनेंगी जो बेहतर राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेंगी। मुख्य न्यायाधीश ने छात्रा को एक पत्र के साथ संविधान की एक हस्ताक्षरित प्रति भेजी है।

संक्षिप्त समाचार

साइबेरिया में हुआ 'चमत्कार', 24 हजार साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद फिर जीवित हुआ सूक्ष्म जीव

वॉशिंगटन, एजेंसी । साइबेरिया में एक सूक्ष्म जीव 24 हजार साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद फिर से जीवित हो गया है. बडेलॉइड रोटिफायर नाम का यह पशु फिर से जीवन में वापस आ गया है. रूसी वैज्ञानिकों के मुताबिक यही नहीं इसने सफलतापूर्वक अपना क्लोन भी तैयार कर लिया है. Current Boilogy जर्नल में छपे अध्ययन में इसका जिक्र किया गया है. अध्ययन की संयुक्त लेखक ए स्टास मालाविन ने एएफपी को बताया कि इस स्टडी से कई सवालों को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है. आखिर ये बहुकोशिका वाले पशु लंबे समय तक जीवित रहने के लिए तंत्र का प्रयोग करते है. उन्होंने कहा, 'हमारी रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि आज भी बहुकोशिकीय पशु क्रिप्टोबायोसिस अवस्था में हजारों साल तक जीवित रह सकते है. क्रिप्टोबायोसिस वह अवस्था है, जिसमें मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है.' यह अध्ययन रूस के साइकोकेमिकल एंड बायोलोजिकल प्रॉब्लम्स इन सॉयल साइंस इंस्टीट्यूट ने किया है.

रूसी आर्कटिक से लिया गया सैंपल- रिसर्च टीम ने ड्रिल करने वाली विशाल मशीन का इस्तेमाल करते हुए रूसी आर्कटिक की अलाजेया नदी के पास से सैंपल जुटाए. इसके बाद रेडियोकार्बन डेटिंग के माध्यम से इसकी उम्र का पता लगाया. इसके मुताबिक इसकी आयु 23,960 से लेकर 24,485 साल के बीच है. इससे पहले इन्होंने इसी तरह के सिंगल सेल माइक्रोब्स की पहचान की थी. बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो ऐसी खबरें है कि नेमाटोड नाम का कीड़ा 30,000 साल के बाद फिर से जीवित हो गया. इसके अलावा काई और अन्य पौधे भी हजारों साल तक बर्फ में दबे होने के बाद फिर से बढ़ने लगे.

इस सूची में नया नाम हुआ शामिल- रोटिफायर को भी अब इस सूची में शामिल कर लिया गया है. इस सूची में वो जीव हैं, जो अनिश्चितकाल तक जीवित रह सकते हैं. खास बात यह है कि यह जीव जीवन में लौटने के बाद बिना किसी मदद के प्रजनन करने में सक्षम था. इस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. रोटिफायर लंबाई में आधा मिलीमीटर है और आमतौर पर ये स्वच्छ पानी वाले वातावरण में रहते हैं.

इस तरह रखा गया नाम- इस जीव का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका इस्तेमाल 'व्हील बियरर' के लिए होता है. यह दिखने में एक घूमते पहिए जैसा होता है. वे घूम-घूमकर ही खाना खाते हैं. मालाविन ने कहा, 'हम इस जीव का उपयोग बर्फ में जमे जीवों का अध्ययन करने के लिए होता है. इसके जरिए अन्य जीवों से भी तुलना की जा सकती है.'

कोरोना पाबंदियां हटाने वाले देशों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई चिंता

जिनेवा (संयुक्त राष्ट्र) । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों पर कड़ी आपत्ति जताई है जहां व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है और इसकी वजह से वहां पर पाबंदियां हटाई जा रही हैं। संगठन के महानिदेशक टैड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि एक तरफ वैक्सीनेशन में अग्रणी रहने वाले देश अपने यहां पर कोरोना संबंध पाबंदियां हटा रहे हैं वहीं दुसरी तरफ कई देशों में हालात लगातार खतरनाक बने हुए हैं। उनके मुताबिक कई तरह की परेशानियों की वजह से इन देशों में कोरोना महामारी का प्रभाव लगातार जारी है। ऐसे में वायरस के बदलते रूप के उभरने का भी जोखिम काफी बढ़ जाता है। ये अब के उपचार को भी बेअसर कर सकता है। महानिदेशक घेब्रेयेसस ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वैक्सीन का असमान वितरण सिर्फ उनके लिए समस्या नहीं है जहां पर इनकी उपलब्धता कम या बिल्कुल नहीं है। संगठन के मुताबिक संक्रमण से मरने वालों की संख्या में बीते छह सप्ताह के दौरान कमी आई है। उनके मुताबिक ये संकेत काफी अच्छे है लेकिन कुछ देशों में कोविड से मरने वालों की संख्या में तेजी भी आई है। इनमें अफ्रीका, अमेरिकी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र शामिल है। उनका कहना है कि कई देशों में अब भी महामारी के हालात अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर गुटारेस ने आग्रह किया है कि वायरस के बदलते प्रकारों के मद्देनजर पाबंदियों को हटाने में सावधानी अधिक रखनी होगी। ये फैसला उन लोगों के लिए घातक हो सकता है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है।

इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि अब तक धनी देशों में 44 फीसद आबादी को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है जबकि गरीब देशों में ये केवल 0.4 फीसद ही है। उन्होंने अमीर देशों से एक बार फिर से अपील की है कि वो अपने यहां पर मौजूद वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक को दान में देने की अपील की है। उनका कहना है कि संगठन सभी देशों को न्यायसंगत तरीके से वैक्सीन उपलब्ध करवाना चाहता है। संगठन प्रमुख ने अपील की है कि सितंबर 2020 तक 10 फीसद वैश्विक आबादी को कम से कम टीका लग जाए। दिसंबर में इसको 30 फीसद किया जाएगा। हालांकि सितंबर के लक्ष्य को पाने के लिए 25 करोड़ अतिरिक्त खुराक की जरूरत होगी।

कोरोना के स्रोत की जांच पर बोला डब्लूएचओ, और जानकारी देने के लिए चीन को नहीं कर सकते मजबूर

जिनेवा । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस के स्त्रोत के बारे में और आंकड़े उजागर करने के लिए डब्लूएचओ चीन को मजबूर नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन इस बात को समझने के लिए अध्ययन की जरूरत का प्रस्ताव करेगा कि अगले स्तर पर वायरस का उभार कहां हुआ। डब्लूएचओ के इमरजेंसी प्रोग्राम के निदेशक माइक रेयान ने प्रेस कांफ्रेंस में जब पत्रकारों ने सवाल किया कि और ज्यादा जानकारी देने के लिए संगठन चीन को कैसे मजबूर करेगा तो उन्होंने कहा कि डब्लूएचओ के पास इस संबंध में किसी को मजबूर करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, इस प्रयास में हम सभी सदस्य देशों की ओर से पूरे सहयोग, जानकारियों और सहायता की अपेक्षा करते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के स्त्रोत को लेकर दो तरह की बातें की जा रही हैं। पहली यह कि यह वायरस जानवरों से मनुष्य में आया है, संभवतः चम्गादड़ों से। दूसरी यह कि यह वायरस चीन में वुहान स्थित प्रयोगशाला से निकला है। वायरस के स्त्रोत का पता लगाने के लिए इस साल की शुरुआत में चीन की यात्रा करने वाली डब्लूएचओ की टीम के सदस्यों का कहना है कि उन्हें सभी आंकड़े मुहैया नहीं कराए गए। इससे चीन की इस मामले में पारदर्शिता को लेकर बहस गर्म हो गई है।

विदेश से चीनी वैक्सीन लगवाकर भारत में फंसे हैं 300 से अधिक भारतीय, चीन नहीं जारी कर रहा वीजा परमिट

बीजिंग । चीन में नौकरी या व्यापार करने वाले 300 से अधिक भारतीय चीनी वैक्सीन लेने के बावजूद चीन में अपने परिवारों के पास पहुंचने के लिए हर तरह की परेशानी उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक चीनी प्रशासन ने उन्हें चीन में वापसी के लिए वीजा परमिट जारी नहीं किया है। विगत 15 मार्च को चीन ने भारत और 19 अन्य देशों से आए सभी यात्रियों के लिए चीन की अपनी कोविड वैक्सीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नई दिल्ली में चीनी दूतावास ने नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि 15 मार्च से लागू प्रतिबंधों को देखते हुए भारत में चीनी दूतावास और कंसुलेटों चीनी वैक्सीन लगवा चुके लोगों को अपना वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट लेना होगा। इसके बाद ही उन्हें चीन लौटने के लिए परमिट वीजा मिलेगा। इस घोषणा के बाद से सैकड़ों भारतीय चीन में अपने कामकाज और व्यापार के लिए जाने को परेशान है। चीन की शर्त को देखते हुए करीब 202 भारतीयों ने आसपास के नेपाल, मालदीव और दुबई जैसे देशों में जाकर मोटी रकम खर्च करके चीन का टीका लगवाया है। चूंकि भारत में चीन की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि इतनी जद्दोजहद के बावजूद इन 300 भारतीयों को राहत नहीं मिली है। चूंकि चीन ने अभी तक वीजा परमिट जारी करना शुरू नहीं किया है। चीनी वैक्सीन लगवा चुके भारतीयों ने चीन प्रशासन से वहां पहुंचकर क्वारंटाइन नियमों का पालन करने और दूसरा टीका भी समय रहते लगवाने का वादा किया है।

आतंकी समूह हिज्बुल्लाह का गठन करने वाले मौलवी अली अकबर की मौत

डमस्कस । आतंकी संगठन हिज्बुल्लाह के संस्थापक मौलवी अली अकबर की कोरोना से मौत हो गई है. मौलवी अली अकबर कभी सीरिया में ईरान का राजदूत भी था. 74 साल की उम्र में अली अकबर की मौत हुई है. मौलवी अल अकबर इरान के सर्वोच्च नेता रहे अयोतुल्लाह रुलाह खोमानी के काफी करीबियों की लिस्ट में शुमार था. साल 1970 में अली अकबर ने मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप के साथ गठजोड़ किया था.

अली अकबर की मौत नॉर्थ तेहरान के एक अस्पताल में हुई है. अली अकबर के बारे में बताया जाता है कि वो अक्सर काला लिबास पहनना पसंद करते था. ताकि वो खुद को इस्लाम के पैंगम्बर मुहम्मद का अनुयायी बता सके. बताया जाता है कि इरान में हुए विवादित चुनाव के बाद मौलवी अली अकबर पिछले करीब 10 सालों से इराक के पवित्र शहर कहे जाने वाले सिटी ऑफ नजफ में रहता था. एक बम हमले में उसका दाहिना हाथ भी खराब हो गया था.

हिज्बुल्लाह वहीं आतंकी संगठन है जिसपर साल 1983 में बेरूत स्थित यू.ए. एंबेसी पर हमला करने का आरोप लगा था. इस हमले में 63 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद यू.एस. की तरफ से किये गये जवाबी हमले में 241 लोगों की मौत हुई थी. उस वक्त हिज्बुल्लाह ने हमले में अपनी संलिप्ता से इनकार किया था. इरान में अगले हफ्ते होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लीडिंग उम्मीदवार कहे जाने वाले इब्राहिम रेसी ने मौलाना अली अकबर की मौत पर अपनी संवेदना जाहिर की है.

बता दें कि साल 1947 में तेहरान में जन्म लेने के बाद अली अकबर की मुलाकात खोमानी से एक मौलवी के तौर पर हुई थी. इसके बाद वो धीरे-धीरे खोमानी का करीबी बन गया. साल 1982 में खोमानी ने अली अकबर को सीरिया में तैनात किया था. इस्लामिक क्रांति के बाद अली अकबर ने इरान में Paramilitary Revolutionary Guard की स्थापना में सहयोग किया. सीरिया का राजदूत रहते हुए उन्होंने इस फोर्स को हिज्बुल्लाह की मदद से काफी बढ़ाया. इरान में हुए ग्रीन मूवमेंट आंदोलन के दौरान अली अकबर ने वहां के तत्कालीन नेता विपक्ष मीर हुसैन मौसावी और माहदी कारौबी की मदद की थी. साल 1979 के इरान आंदोलन में सक्रिय रहने वाला अली अकबर ने बाद में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इरान में अंदरुनी मामलों के मंत्री का पद भी संभाला था.

प्रिंस हैरी-मेगन मार्कल की बेटी लिली के जन्म पर क्वीन एलिजाबेथ ने दी बधाई

लंदन । प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल एक बार फिर माका-पिता बन गए हैं. मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और शाही परिवार ने राजकुमार हैरी और मेगन मार्कल की बेटी लिलिबेट लिली डायना माउंटबेटन-विंडसर के जन्म पर उन्हें बधाई दी. हैरी और मेगन दंपति की यह दूसरी संतान है. उनका दो साल का बेटा आर्ची हैरिसन माउंटबेटन-विंडसर है. बकिंघम पैलेस ने एक बयान में बताया कि हैरी के पिता राजकुमार चार्ल्स और भाई राजकुमार विलियम समेत शाही परिवार ने शुक्रवार को लॉस एंजिलिस में ड्यूक और डचेज ऑफ ससेक्स की बेटी के जन्म पर खुशी जतायी. हैरी और मेगन की दूसरी संतान का नाम महारानी और दिवंगत दादी प्रिंसेस डायना के नाम पर रखा गया है. महारानी को उनके परिवार के लोग प्यार से लिलिबेट बुलाते थे. बयान के अनुसार, लिलिबेट डायना के जन्म पर बधाई ड्यूक और डचेज ऑफ ससेक्स को बधाई. इसके अनुसार, महारानी, प्रिंस ऑफ वेल्स (चार्ल्स) एवं डचेज ऑफ कॉर्नवाल (कैमिला) और ड्यूक एवं डचेज ऑफ कैम्ब्रिज (विलियम और केट मिडलटन) इस खबर से बेहद प्रसन्न हैं. विलियम और केट ने अपने केनसिंगटन पैलेस से ट्वीट कर कहा, बेबी लिली के आने की खुशखबरी से हम सब रोमांचित हैं.

विपक्षी गठबंधन के सरकार बनाने पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले- ये इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी फ्रॉड

यरूशलम । इजरायल में एक दशक से यादा वक्त तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू अब सत्ता के आखिरी दिनों में हैं. विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ गठबंधन बना लिया है और सरकार गठन की तैयारी में हैं. इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने विपक्ष के सरकार बनाने के फैसले को लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी फ्रॉड करार दिया है. नेतन्याहू ने यह आरोप ऐसे वक्त में लगाया है, जब इजरायल के सिक्योरिटी चीफ ने राजनीतिक हिंसा होने की आशंका जताई है. नेतन्याहू ने यह आरोप विपक्षी दलों के चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को लेकर लगाया है. उनकी जगह पीएम बनने जा रहे नफ्ताली बेनेट ने प्रचार के दौरान कहा था कि वह लेफ्ट विंग, मध्यमार्गी पार्टियों और अरब पार्टी के साथ साझेदारी नहीं करेंगे.

अब वह इन्हीं दलों के साथ गठबंधन कर पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं. इसी को लेकर नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि यह इलेक्शन फ्रॉड है. विपक्षी गठबंधन के बीच पीएम पद को लेकर रोटेशन का फैसला हुआ है. पहले दो साल तक बेनेट पीएम रहेंगे और फिर अगले दो साल तक याइर लुपिड देश की कमान संभालेंगे. नई सरकार के लिए संसद में वोटिंग का दिन अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 14 जून को नए पीएम शपथ ले सकते हैं. इस साल 23 मार्च को चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था.

बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी लिकुड पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, हम देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनावी फ्रॉड देख रहे हैं. मेरी राय में तो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ है. नेतन्याहू ने कहा कि इसके चलते लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं. उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता. उनका साफ इशारा बेनेट की ओर से किए गए उन वादों को लेकर था, जिनमें उन्होंने कहा था कि वह लैपिड या अन्य लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे. बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू 2009 से ही इजरायल के पीएम के तौर पर काम कर रहे हैं.

तानाशाह किम जोंग उन का अजीबोगरीब फरमान, ये सब किया तो मिलेगी मौत की सजा...

प्योंगयांग । उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में एक नए कानून को पेश किया है. इसके तहत उत्तर कोरिया में विदेशी प्रभाव को खत्म करने के लिए विदेशी फिल्में, कपड़े और अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करने पर मौत की सजा से लेकर जेल की सजा का प्रावधान किया है. किम जोंग उन ने एक व्यक्ति को केवल इसलिए मौत सजा दे दी थी कि क्योंकि उसे दक्षिण कोरियाई फिल्म के साथ पकड़ा गया था. यून मि सो उस समय 11 साल की थीं जब उत्तर कोरियाई व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया था.

इस दौरान उसके पूरे पड़ोस को आदेश दिया गया था कि वे सजा-ए-मौत की पूरी प्रक्रिया को देखें. सो ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि अगर आप मौत की सजा को नहीं देखते हैं तो इसे राजद्रोह माना जाएगा. उत्तर कोरियाई गार्ड यह सुनिश्चित कर रहे थे कि सभी लोग यह जान लें कि अश्लील वीडियो को तस्करी करके लाना मौत की सजा दलिा सकता है.

सो ने कहा कि यह देखना उनके लिए बहुत पीड़ादायक था. मेरी आंखों में पानी आ गए थे. उत्तर कोरियाई सैनिक उस व्यक्ति को गोली मार दिए थे. आप कल्पना करें एक ऐसा देश जहां लगातार सरकार की ओर से लॉकडॉउन लगाया जाता है और इंटरनेट भी नहीं होता है. वहां कोई सोशल मीडिया नहीं है और केवल कुछ सरकारी टीवी चैनल हैं जो यह बताते रहते हैं कि देश के नेता आपसे क्या सुनना चाहते हैं. यह स्थिति उत्तर कोरिया की है.

अब किम जोंग उन के प्रशासन ने प्रतिक्रियावादी विचारों के खिलाफ नया कानून बनाया है. अगर किसी को दक्षिण कोरिया, अमेरिका या जापान की मीडिया सामग्री रखते पाया गया तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी. यही नहीं इसे जो लोग देखते हुए पकड़े जाएंगे उन्हें 15 साल की सजा हो सकती है. हाल ही में किम ने एक पत्र लिखकर कहा कि देश का यूथ लीग युवाओं में समाजवाद विरोधी विचारधारा के खिलाफ ऐक्शन ले.

किम युवाओं में विदेशी भाषण, हेयर स्टाइल और कपड़ों के प्रसार को रोकना चाहता है. उसने इसे खतरनाक जहर करार दिया है. दक्षिण कोरिया के डेली एनके मुताबिक इन किशोरों को इसलिए री एजुकेशन कैंप में भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने कोरियाई पॉप स्टार्स की तरह से बाल कटाए हुए थे. बीबीसी के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि किम जोंग उन ने बाहरी सूचनाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है.

अमेरिका में 20 साल के विचार के बाद अल्जाइमर की दवा को मंजूरी, मस्तिष्क के धीरे-धीरे नष्ट होने पर किया जा सकेगा काबू

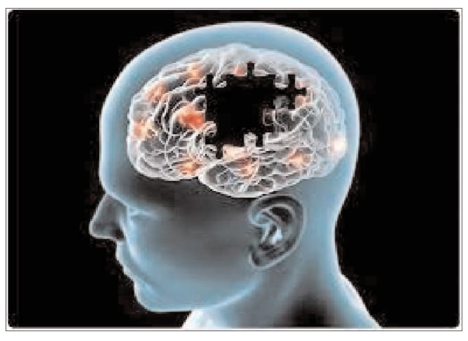

वाशिंगटन । अमेरिका में सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने करीब 20 साल चले विचार-विमर्श के बाद अल्जाइमर की बीमारी के इलाज के लिए नई दवा स्वीकृत कर दी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने कहा है कि बायोजेन कंपनी द्वारा विकसित दवा के इस्तेमाल को स्वीकृति दी जा रही है।

अल्जाइमर मस्तिष्क को धीरे-धीरे नष्ट करने वाली बीमारी है जिसमें पीड़ित शरीर पर अपना नियंत्रण खोता चला जाता है। एफडीए ने कहा है कि नई दवा से बीमारी का असर धीमा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसके दुष्प्रभाव भी कम होंगे। इस फैसले से लाखों वृद्ध अमेरिकी नागरिकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

यह नई दवा बायोजेन ने जापान की आइसाई कंपनी के साथ मिलकर तैयार की है। यह मस्तिष्क को हो चुके नुकसान की भरपाई तो नहीं करेगी, लेकिन भविष्य में होने वाले नुकसान की गति को धीमा जरूर करेगी। यह दवा हर चार सप्ताह में एक बार देनी होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस दवा से डिमेंशिया के मरीजों को भी फायदा होगा। यह उनमें स्मरण शक्ति क्षीण होने की गति कम करेगी।

खैबर पख्तूनख्वा में दर्दनाक हादसा, पहाड़ से नीचे सिंधु नदी में जा गिरी यात्रियों से भरी वैन, 17 लोगों की मौत

इस्लामाबाद , एजेंसी । पाकिस्तान के पर्वतीय प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां यात्रियों से भरी एक वैन नदी में गिर गई. इस दुर्घटना में कम से कम 17 यात्रियों की मौत हो गई. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, वैन चिलास से रावलपिंडी जा रही था, इसी दौरान ये कोहिस्तान जिले के पनिबा इलाके में सिंधु नदी में गिर गयी. इस वैन में ड्राइवर समेत 17 लोग सवार थे और इसे एक परिवार ने निजी तौर पर यात्रा के लिए बुक किया था.

बताया गया कि ये हादसा तब हुआ जब ड्राइवर ने एक तीखा मोड़ लिया. लेकिन इस दौरान ड्राइवर ने वैन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से यात्रियों से भरी वैन नदी में गिर गई. पुलिस ने बताया कि वैन सिंधु नदी की ओर मुड़ गई और फिर गिरने के बाद इसमें डूब गई. इसने आगे बताया कि इस घटना में सभी 17 लोग मारे गए. बचाव दल लापता यात्रियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मुश्किल इलाके और नदी की गहराई के कारण उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. देश के उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें कुछ सबसे खतरनाक पहाड़ों से होकर गुजरती हैं, जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं.

दो दिन पहले सिरेन नदी में गिरी वैन

इससे पहले, रविवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मानसेहरा जिले में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. दरअसल, पर्वतीय रास्ते से एक मिनीवैन सिरेन नदी में जा गिरी. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए. बचाव सेवा के प्रवक्ता अहमद फैजी ने बताया कि दो महिलाओं, एक बच्चा और चार पुरुषों के शव बरामद किए गए. वहीं घायल तीन बच्चों को फुलरा कस्बे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. सड़कों की खराब स्थिति और यातायात के नियमों का पालन नहीं करना अक्सर ही हादसों की वजह बनता है.

पिछले हफ्ते दो सड़क हादसों में 10 लोगों की हुई मौत- वहीं, पिछले हफ्ते शुक्रवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में पाकिस्तान में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 16 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए. एक हादसा सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में हुआ. यहां तेज रफ्तार कार और बस की टक्कर हो गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हुए. हादसा कार का टायर फटने के कारण हुआ था. घटना की जानकारी मिलने के बाद बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए थे. वहीं, दूसरा हादसा लाहौर में फिरोजपुर रोड पर हुआ था. यहां एक बस और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई. जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई. चारों मृतक एक ही परिवार के थे.

प्रेस का 'गला घोंटने' वाले चीन-पाकिस्तान लॉन्च करेंगे मीडिया हाउस, आसियान की मेजबानी कर 'ड्रैगन' चल रहा नई चाल

पेइचिंग , एजेंसी। प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंटने वाले पाकिस्तान और चीन एक टेलीविजन चैनल और मीडिया संगठन तैयार करने की योजना बना रहे हैं. इसका मकसद सूचना पर अपना अधिकार जमाना और पश्चिमी मीडिया का एक विकल्प देना है. इसके लिए प्रधानमंत्री इमरान खान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार पैसा देगी. दूसरी ओर, दक्षिण एशिया में चीन और अमेरिका में जारी होड़ के बीच बीजिंग ने बड़ा दांव खेल दिया है. चीन इस हफ्ते आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने वाला है.

पाकिस्तान और चीन कतर के अल-जजीरा और रूस के ऋ्ज्ञ नेटवर्क की तरह एक मीडिया संगठन को तैयार करने की संभावना को तलाश रहे हैं. इस मीडिया हाउस में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकारों को शामिल करने की योजना है, जिन्हें चीनी सरकार से फंडिंग मिलेगी. इस मामले से संबंधित लोगों ने इसकी जानकारी दी. इसकी जानकारी रखने वाले लोगों ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हासिल किए गए दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि इस कदम के पीछे सोच ये है कि चीन के आंतरिक हालात फ्री मीडिया को रोकते हैं, लेकिन देश में वित्तीय ताकत है. दूसरी ओर, पाकिस्तान के आंतरिक हालात ऐसे मीडिया संगठन के लिए अनुकूल है, लेकिन देश में वित्तीय संसाधनों की कमी है.

दोनों देशों को लगता है कि अल-जजीरा और ऋ्ज्ञ के कद के एक मीडिया हाउस की जरूरत है, ताकि अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा सके. ऐसा मीडिया संगठन पाकिस्तान में स्थापित किया जा सकता है और दोनों पक्षों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चीन द्वारा इसे फंडिंग मिल सकती है. बता दें कि दो साल पहले पाकिस्तान ने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक अंग्रेजी टेलीविजन लॉन्च करने की योजना बनाई थी. इसकी चैनल के जरिए इस्लाम की सही इमेज और इस्लामोफोबिया से निपटने की योजना थी. इमरान खान ने खुद तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन और मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद से 2019 में बात की थी.

अबू नासिर परिवार के सदस्य अपने घर के अंदर बैठते हैं, गाजा पट्टी के बेत हानौन में गाजा के हमास शासकों और इजरायल के बीच 11 दिनों के युद्ध के दौरान हवाई हमलों से भारी क्षति हुई है।

मुस्लिम परिवार को निशाना बनाकर वाहन से रौंदा, चार की मौत, पीएम ट्रूडो बोले- 'देश में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं'

वॉशिंगटन, एजेंसी । कनाडा में पैदल जा रहे मुस्लिम परिवार के पांच लोगों को एक व्यक्ति ने अपने वाहन से टक्कर मार दी. घटना में परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी और एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है. कनाडा की पुलिस ने सोमवार को इस बारे में बताया. आरोप है कि वाहन चालक ने परिवार को मुस्लिम होने के कारण निशाना बनाया. घटना रविवार शाम में हुई. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वह घटना से भयभीत और हैरान हैं.

ओंटारियो में पुलिस ने बताया कि पीड़ितों में 74 वर्षीय महिला, 46 वर्षीय पुरूष, 44 वर्षीय महिला और 15 वर्षीय लड़की शामिल है. नौ साल का बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. वहीं, परिवार ने नाम जाहिर नहीं करने का अनुरोध किया है.

इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उस पर चार लोगों की हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि संदिग्ध 20 वर्षीय नाथानील वेल्टमैन ओंटारियो में लंदन का रहने वाला है.

पुलिस ने बताया कि वाहन ने एक मोड़ पर पीड़ितों को रौंद दिया. पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को पास के एक मॉल के पार्किंग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. लंदन पुलिस के प्रमुख स्टीफन विलियम्स ने कहा, हमारा मानना है कि पीड़ितों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे मुस्लिम हैं. किसी भी समुदाय को नफरत की भावना से निशाना बनाया जाये तो समुदाय विशेषकर मुस्लिमों में डर और घबराहट पैदा हो सकती है.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने परिवार पर हुए हमले को नफरत भरी बताया और कहा कि वह इस घटना से भयभीत और हैरान हैं. उन्होंने कहा, वह इस घटना में बचने वाले बच्चे समेत पीड़ितों के प्रियजनों के साथ हैं और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं. ट्रूडो ने ट्वीट कर कहा, 'लंदन में रहने वाले मुस्लिम समुदाय और देशभर के मुस्लिम जानते हैं कि हम उनके साथ हैं. इस्लामोफोबिया की हमारे समुदाय के बीच कोई जगह नहीं है. ये नफरत कपटी और घिनौनी है और इसे रोका जाना चाहिए.'

मुस्लिमों के खिलाफ घटनाओं में हुई वृद्धि- हाल के महीनों में अलबर्टा प्रांत में मुस्लिम महिलाओं को मौखिक और शारीरिक शोषण की कई घटनाओं में निशाना बनाया गया है. सितंबर में 58 वर्षीय मोहम्मद-असलीम जफीस को टोरंटो के वेस्ट एंड की एक मस्जिद के बाहर चाकू मारा गया. यहां पर वह एक केयर टेकर के रूप में काम करती थीं. इस घटना ने अधिकारियों पर दबाव बनाया कि वह दक्षिणपंथी हिंसा के खतरे को गंभीरता से लें और इस तरह के हमलों की जांच करें.

वहीं, 2017 में क्यूबेक सिटी में एक मस्जिद के बाहर गोलीबारी की गई थी. इस घटना में छह मुस्लिम व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

अरविंद केजरीवाल ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, राष्ट्रहित के कामों में मैंने आपका साथ दिया, आप भी दीजिए

नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी घर-घर राशन योजना के मुद्दे पर लिखी गई है। पत्र में सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील करते हुए लिखा है कृपया घर-घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने दीजिए। आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया है, राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए।

इस पत्र के माध्यम से केजरीवाल ने घर-घर राशन योजना को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यह योजना पूरे देश में लागू हो। केंद्र सरकार इस योजना में जो बदलाव करवाना चाहती है हम वो करने के लिए तैयार हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी से राशन की होम डिलीवरी (डोर स्टेप डिलीवरी) योजना पर लगी रोक को हटाने की अपील की थी। सीएम ने कहा कि राशन को हर गरीब आदमी के घर तक पहुंचाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। अगले सप्ताह योजना शुरू होनी थी, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। उन्होंने सवाल किया कि जब लोगों के घर पिजा और बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, तो गरीब लोगों के घर राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? दरअसल केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी 'घर-घर राशन योजना' (डोर स्टेप डिलीवरी) पर अभी हाल में ही रोक लगा दी थी। यह योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई है। इसलिए इस पर रोक लगाई गई है।

बता दें कि इससे पहले राशन योजना के नाम को लेकर भी केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए था कि यह योजना केंद्र की योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है। इसमें कोई भी बदलाव केवल संसद कर सकती है, न कि राय। इसलिए दिल्ली सरकार इस योजना का न तो नाम बदल सकती है और न ही इसको किसी और के साथ जोड़ सकती है। केजरीवाल सरकार इस योजना को 25 मार्च को लागू करना चाह रही थी, लेकिन केंद्र की आपत्ति के कारण यह संभव नही हो पाया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन' योजना से बदलकर 'घर-घर राशन' योजना रख दिया था।

नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो सेवाओं को क्रमबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के बाद बाराखंभा मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतार में खड़े लोग।

संक्षिप्त खबर

नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, ट्रामाडोल की 42,000 गोलियां जब्त

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने यहां कश्मीरी गेट इलाके से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 42,000 गोलियां जब्त करके नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ट्रामाडोल को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत नशीले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है. पुलिस ने बताया कि दो जून की रात को कश्मीरी गेट पर वाहनों की जांच कर रही एक पुलिस टीम को एक खड़ी कार पर संदेह हुआ. कार को खड़ा किए जाने का कारण पूछे जाने पर उसमें बैठे तीन लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार की तलाशी लेने पर उसमें से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के 74 डिब्बे मिले.

दिल्ली में नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ था- वहीं, पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने पांच लोगों की गिरफ्तारी और करीब 250 करोड़ रुपये की 54.2 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने के साथ एक अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. पुलिस के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि गिरफ्तार किए गए पांच लोगों की पहचान अल्ताफ उर्फ मेहराजुद्दीन दर्जी, आबिद हुसैन सुल्तान, हशमत मोहम्मदी, तिफल नाउ खेज और अब्दुल्ला नजीबुल्लाह के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में एक ड्रग फैक्ट्री होने का भी दावा किया था. दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों तस्करी के मामले बढ़ गए हैं. बीते 8 मई को भी खबर सामने आई थी कि दिल्ली में नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ है.

पड़ोसी ने डराकर महिला के साथ किया रेप, एफआईआर के बाद आरोपी गिरफ्तार

नोएडा। देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. नोएडा फेस 2 के भंगेल इलाके में एक महिला ने छत पर सो रहे अपने पति के इंतजार में कमरे का दरवाजा खुला रखा था, लेकिन इस बीच पड़ोस में रहने वाले शख्स ने कमरे में घुसकर न सिर्फ उसे डराया धमकाया बल्कि रेप भी कर दिया. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. नोएडा पुलिस के मुताबिक, भंगेल इलाके एक महिला अपने कमरे में सो रही थी. जबकि उसका पति सोने के लिए छत पर चला गया था. इस बीच महिला ने इस उम्मीद के साथ दरवाजा खुला रखा कि उसका पति रात में नीचे आएगा, लेकिन उसके साथ पड़ोस में रहने वाले रिंकू ने रेप की वारदात को अंजाम दे दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

महिला को डराकर किया रेप- पुलिस के मुताबिक, महिला के पड़ोस में रहने वाले रिंकू दरवाजा खुला देख कमरे में चुपचाप घुस गया और डरा धमकाकर रेप कर दिया. इसके बाद महिला और उसके पति ने अपने पड़ोसी के खिलाफ रेप करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद आरेपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ जारी है. वहीं, पीड़ित महिला का जिला अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया गया है. हालांकि पुलिस इस मामले की दूसरे एंगल से भी जांच करने के साथ महिला के पड़ोसियों से भी पूछताछ करने का प्लान बना रही है.

भाजपा ने अपने अध्यक्ष से लगाई गुहार, कहा- व्यापारियों को कमर्शियल प्रॉपर्टी पर मिले टैक्स में छूट

नई दिल्ली । कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिल्ली में करीब 2 माह से लॉकडाउन लागू है. केजरीवाल सरकार ने अब लॉकडाउन के साथ अनलॉक की शुरुआत की है. ऐसे में व्यापारियों को राहत देने की गुहार भी लगाई जा रही है. दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाई है कि सभी दुकानों और फैक्ट्रियों के बिजली के फिक्स्ड चार्ज पर राहत दी जाए. उन्होंने सीएम केजरीवाल से आग्रह किया है कि दिल्ली के सभी दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों के अप्रैल से जून माह तक के बिजली के फिक्स्ड चार्ज को माफ किया जाए. वहीं, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के भी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिजली के फिक्स्ड चार्ज माफ किए जाएं. भाजपा प्रवक्ता कपूर ने अपनी ही पार्टी भाजपा शासित नगर निगमों से भी संपत्ति कर में छूट देने की मांग की है. प्रवक्ता की ओर से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता से आग्रह किया है कि वर्ष 2021-22 के लिए कमर्शियल संपत्तियों से नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स रिहायशी दर पर लेकर छूट दे. इससे उन सभी दुकानदारों, व्यापारियों को बड़ी राहत मिल सकेगी जो कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन में वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं.

निगम शिक्षकों के काम की खबर, लैपटॉप खरीदने पर मिलेगी 10 हजार की सब्सिडी

नई दिल्ली । कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद हैं. ऐसे में स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है. ईस्ट एमसीडी ने भी अपने बंद स्कूलों के बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए लेपटॉप खरीद पर 10,000 की सब्सिडी देने का निर्णय किया है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने निगम स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अहम फैसला किया है. शिक्षा समिति के अध्यक्ष रोमेश गुप्ता ने कहा है कि पूर्वी निगम सभी निगम शिक्षकों को लैपटॉप खरीदने के लिए प्रति लैपटॉप दस हजार रुपए की सब्सिडी देगा. पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन और स्थायी समिति अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने इस संबंध में अग्रिम मंजूरी प्रदान कर दी है. रोमेश गुप्ता ने बताया कि कोविड के चलते निगम स्कूल भी बंद है. लेकिन ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से छात्रों को लगातार पढ़ाया जा रहा है. पिछले सत्र में व्हाट्सअप, विडियो और मोबाइल के सहारे बच्चों को पढ़ाया गया. हालांकि, इस दौरान यह महसूस किया गया कि अच्छे संचार साधनों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण और भी गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है. लिहाजा लैपटॉप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निगम ने दस हजार रुपए प्रति लैपटॉप की सब्सिडी देने का फैसला किया है.

हाईकोर्ट का निर्देश ड्रग तस्कर को चिकित्सा के आधार पर नहीं मिलेगी जमानत, जेल के अंदर करें इलाज

नई दिल्ली । ड्रग तस्करी के मामले में जुलाई 2019 में गिरफ्तार किए गए अफगानी ड्रग तस्कर मोहम्मद अकबर की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि आरोपित ने चिकित्सकीय आधार पर जमानत की मांग की है, लेकिन इससे जुड़ा कोई भी दस्तावेज नहीं पेश किया है। हालांकि, पीठ ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि अगर आरोपित को तत्काल इलाज या सर्जरी मामले उपलब्ध कराने की जरूरत है और जेल अस्पताल में सुविधा नहीं है तो सरकारी अस्पताल में हिरासत में इलाज कराया जाये। मोहम्मद अकबर ने याचिका दायर कर कहा कि उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और उसे जल्द ही सर्जरी कराना है।

अकबर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते समय चिकित्सकीय स्थिति को नहीं देखा। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित को 329.55 ग्राम मात्रा के ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया था और वह ड्रग तस्करी के बड़े गिरोह का सदस्य है। इतना ही नहीं आरोपित के साथ गिरफ्तार किए गए अहमद शाह अलोकोजी व नेदा मोहम्मद को जमानत पर रिहा किया गया था और वे फरार हैं। अदालत द्वारा उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपित अकबर अफगान का है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह भी मुकदमे से भाग सकता है।

याचिका के अनुसार स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी जुलाई 2019 में ड्रग तस्कर दीपक समेत अन्य आरोपितों को मजनू का टीला से गिरफ्तार किया था। दीपक की निशानदेही पर मोहम्मद अकबर व नेदा मोहम्मद को हरियाणा के सोनीपत स्थित जेएम कूल हाउस कोंडली से गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने बताया कि वे अफगान से अटारी बार्डर के रास्ते से भारत में ड्राई-फूड के कार्टन में ड्रग की तस्करी करते थे।

दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों पर मार्शल तैनात करने का दिया निर्देश, कोविड नियमों के पालन के लिए सख्ती

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने शहर में सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसे कोविड नियमों को सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मार्शल और स्टाफ तैनात करें. साथ ही सरकार ने शराब दुकानदारों से कहा है कि वे सुरक्षा और आदेशों का पालन करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करें. एक्साइज डिपार्टमेंट ने 6 जून के अपने एक आदेश में कहा, सभी चार सरकारी कॉरपोरेशन DSIIDC, DTTDC, DSCSC और DCCWS अपने सभी दुकानों पर मार्शन तैनात करेंगे और प्राइवेट लाइसेंस वाले अपने कर्मचारियों को तैनात करेंगे, ताकि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जैसे कोविड नियमों का पालन हो सके.÷

आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी शराब दुकान पर शराब, पान, गुटखा या तम्बाकू का इस्तेमाल नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा. दिल्ली में अभी सरकारी एजेंसियों और निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे करीब 850 शराब की दुकानें हैं. इसमें 40 फीसदी दुकानें निजी व्यक्तियों के द्वारा चलाई जा रही हैं. वहीं दिल्ली में शराब बेचने के लिए फिलहाल 4 सरकारी एजेंसी हैं. जिसमें दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लायज कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल शामिल है.

अनलॉक के दूसरे चरण में दिल्ली सरकार ने शराब दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि शहर में शराब दुकानें ऑड-इवन आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी. अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में संशोधन कर शहर में शराब की होम डिलीवरी की भी अनुमति दी थी. दिल्लीवासी मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए शराब का ऑर्डर कर सकेंगे.

कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने तैनात की अपनी टीमें

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करीब डेढ़ महीने की बंदी के बाद बाजार, मॉल और कार्यालय सोमवार से दोबारा खुलने जा रहे हैं, जिसके साथ ही शहर में कोविड-उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने टीमें तैनात की हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा था कि सात जून से दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल सम-विषम आधार पर खुलेंगे. जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण के प्रसार के अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे प्रमुख बाजारों, मॉल और शराब की दुकानों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इन जगहों पर भीड़ एकत्र होने की अधिक संभावना रहती है. उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर कोविड-19 से बचाव संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष तौर पर कर्मियों की तैनाती की जाएगी. दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी

विश्वेंद्र ने कहा, ''सतर्कता उद्देश्यों के लिए 50 टीमों का गठन किया गया है. प्रमुख स्थानों जैसे लाजपत नगर मार्केट में 10 या उससे अधिक टीमें तैनात की जाएंगी क्योंकि ऐसी जगहों पर भीड़ एकत्र होने की अधिक संभावना है.''

अनुपालन करवाने के लिए उल्लंघनकर्ताओं का चालान किया जाएगा

वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सोमवार से अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के मद्देनजर पिकेट की संख्या बढ़ाई जाएगी और गश्त को भी तेज किया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि शराब की दुकानों पर भीड़ एकत्र होने की सूरत में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए अतिरिक्त टीमों को लगाया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 संबंधी बचाव नियमों का अनुपालन करवाने के लिए उल्लंघनकर्ताओं का चालान किया जाएगा.

संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद यह फैसला लिया गया है- दरअसल, दिल्ली में सोमवार (7 जून) से लॉकडाउन के साथ अनलॉक का दूसरा फेज शुरू होगा. हालांकि, अनलॉक का पहला फेज पिछले हफ्ते से शुरू हो गई थी. पहले फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को खोलने की इजाजत दी गई थी. अब सोमवार से कुछ और चीजें खोलने की इजाजत दी गई हैं. 7 जून से बाजार और मॉल्स ऑड-इवन आधार पर खुलने जा रहे हैं, तो वहीं मेट्रो भी 50 फीसदी यात्रियों के साथ शुरू की जा रही है. ई-कॉमर्स के जरिए सामान बेचने की इजाजत भी दी गई है. कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद यह फैसला लिया गया है.

'दिल्ली दंगे राष्ट्र की अंतरात्मा पर गहरा घाव', व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा भड़काने के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान हत्या के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. इस शख्स पर दंगों के दैरान बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप 'कट्टर हिंदू एकता' के जरिए हिंसा को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा है. आरोपी अंकित चौधरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कहा कि आवेदक मौके पर मौजूद था और एक विशेष समुदाय के दंगाइयों को उकसा रहा था, जो उसके उकसाने पर किसी को भी मार सकता था.

अदालत ने कहा कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड की गई चैट को देखा है. अदालत ने आगे कहा, इसमें इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अत्यधिक सांप्रदायिक मालूम होती है और स्पष्ट रूप से एक विशेष समुदाय के सदस्यों के प्रति वैमनस्य, दुश्मनी और घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देती है.

मनमाना और निरंकुश जांच का शिकार हुआ मुवक्किल- यह मामला एक शख्स की हत्या से संबंधित है, जिसके शरीर पर और सिर पर कई चोट के निशान थे. पुलिस को भगीरथ विहार नाला में शव मिला था. आरोपियों के वकील प्रदीप तेवतिया और जितेंद्र बख्शी ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल ÷मनमाना और निरंकुश जांच का शिकार हुआ है. उन्होंने तर्क दिया कि यह इस तथ्य से साफ होता है कि इस मामले के अलावा, उसे हत्या के आठ अन्य मामलों में झूठा फंसाया गया है. आवेदक को केवल ÷सांप्रदायिक दंगों को रोकने/नियंत्रित करने में राज्य की प्रशासनिक विफलता को छिपाने के लिए जांच एजेंसी द्वारा झूठा फंसाया गया है.

'जंगल की आग की तरह फैले दंगे'- स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राजीव कृष्ण शर्मा ने अदालत को बताया कि आवेदक अपने सेल फोन की लोकेशन के माध्यम से अपराध स्थल पर पाया गया था और वह व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था. अदालत ने कहा, ÷यह सबको पता है कि कि 25/26 फरवरी 2020 के नीरस दिनों में पूर्वोत्तर दिल्ली के कुछ हिस्से सांप्रदायिक उन्माद की चपेट में आ गए, जिनसे विभाजन के दिनों के नरसंहार की याद ताजा हो गई. जल्द ही, दंगे जंगल की आग की तरह राजधानी में फैल गए, नए क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया और अधिक से अधिक निर्दोष लोगों की जान ले ली. दिल्ली दंगे 2020 एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने के इच्छुक राष्ट्र की अंतरात्मा पर गहरा घाव है. आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं.

गौतम गंभीर ने कहा टीकाकरण पर न करें राजनीति, काम करने की इच्छा तो रास्ता मिल ही जाता है

नई दिल्ली । पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने मंगलवार को गीता कालोनी में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। गौतम गंभीर फाउंडेशन अपने खर्च पर जरूरतमंदों को कोरोना रोधी टीका लगवाएगी। हर रविवार झुग्गियों में घर-घर जाकर टीकाकरण होगा। गौतम गंभीर ने कहा कि ये अभियान सिर्फ पूर्वी दिल्ली के नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली के लिए है। टीकाकरण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर काम करने की इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। गौतम गंभीर ने ये बातें किस नेता के लिए कही उसका नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की तरफ ही था।

दरअसल राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप पिछले कई दिनों से जारी है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते कई केंद्रों पर टीकाकरण अभी बंद है। दिल्ली सरकार ने कहा कि दस जून के बाद सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी।

बता दें कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोरोना काल में लोगों की मदद पहले से भी रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए जरुरी दवाइयां भी मुफ्त में देने की शुरुआत की थी। जब ये दवाइयां बाजार में बड़ी मुश्किल से मिल रही थी तब दौ से ज्यादा जरुरतमंदों को वे दवा उपलब्ध करा रहे थे।

नेता प्रतिपक्ष बोले, दिल्ली सरकार ने राशन बांटने के लिए नहीं उठाया कोई कदम, ना ही गरीबों को बांटा, करें कार्रवाई

नई दिल्ली । गरीबों को बांटने के लिए आया हजारों टन अनाज राजधानी के स्कूलों में सड़ रहा है, इसकी जानकारी दिल्ली सरकार को फरवरी में दे दी गई थी। इसके बावजूद सरकार ने न तो इस अनाज को खराब होने से बचाने के लिए कोई कदम उठाया और न ही इसे गरीबों को बांटा गया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पांच फरवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में बताया था कि पिछले साल लाकडाउन के दौरान गरीबों को बांटने के लिए आया अनाज स्कूलों में पड़ा सड़ रहा है। बिधूड़ी ने लिखा था कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में 1200 क्विंटल गेहूं, तीन सौ क्विंटल चावल और तीन हजार राशन किट व तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में 1600 क्विंटल गेहूं-चावल व 1500 राशन किट खराब हो रही हैं। राशन किट में रखा रिफाइंड तेल, मसाले, छोले, चीनी, हल्दी आदि एक्सपायर हो चुके थे।

सीएम कार्यालय से भेजे गए जवाब में कहा गया था कि इस बारे में उपमुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद चार माह तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया और पूरा अनाज खराब हो गया। बिधूड़ी ने कहा कि अनाज की बर्बादी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि स्कूलों में हुई अनाज की बर्बादी संबंधी समाचार पिछले दिनों दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किए हैं। यदि इन अनाजों का वितरण हो जाता तो लाखों कामगार इसका इस्तेमाल कर पाते और उनका पेट भर जाता मगर इस दिशा में कदम ही नहीं उठाया गया जिसका नतीजा ये हुआ कि लाखों टन अनाज खराब हो गया।

अनिश्चित है कोरोना महामारी का आकार, सभी प्रक्रियाओं के स्थायी विकल्प की दरकार

नई दिल्ली । शिक्षा जगत से जुड़े अनुभवी लोगों से विमर्श करके शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने माननीय प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, परीक्षा कराने के विकल्प क्या-क्या हो सकते हैं, इसके लिए ज्ञापन दिया था, परंतु निर्णय जो भी हुआ उसे हमें स्वीकार करते हुए आगे सोचने की आवश्यकता है कि एक वर्ष परीक्षा नहीं होने से देश की शिक्षा और छात्रों के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी पूर्ति कैसे होगी, इस पर मंथन करना होगा।

कोरोना की जब पहली लहर आई थी, तभी से विश्व के अनेक डॉक्टर्स और विज्ञानी लगातार कहते रहे कि यह महामारी तुरंत जाने वाली नहीं है। इसके लिए हमें कोरोना के साथ-साथ जीने के लिए अभ्यस्त होना होगा। अभी यह दूसरी लहर कब तक चलेगी? और तीसरी लहर आयेगी क्या? और आयेगी तो कब तक चलेगी इसके बाद भी क्या होगा, कहना कठिन है। हमने इस प्रकार की स्थितियों में सुरक्षित एवं स्वस्थ रहकर अपने सारे काम चलाने की मानसिक तैयारी एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं निर्माण करने की दिशा में अतिशीघ्रता से कदम उठाने होंगे। हम यहां शिक्षा और परीक्षा की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्वीकार किया है कि वर्तमान बोर्ड की परीक्षाओं से छात्रों पर बोझ एवं तनाव निर्माण होता है उससे मुक्ति पाने के लिए इसमें लचीलापन लाना होगा।

मेरी दृष्टि में मात्र बोर्ड की परीक्षा ही नहीं परंतु सभी स्तर की परीक्षाओं में सतत एवं समग्रता से मूल्यांकन हो। छात्रों का मूल्यांकन मात्र 3 घंटे की रटंत पद्धति से न होकर वर्ष भर छात्र की विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता, उनका आचार-व्यवहार, प्रैक्टिकल कार्य, मौखिक परीक्षा आदि के द्वारा होना चाहिए।

12वीं बोर्ड की परीक्षा हेतु इसी दिशा में सुझाव दिया जा सकता है कि कक्षा 10वीं एवं 11वीं के परिणाम का औसत निकालकर 30 फीसद अंक, आंतरिक मूल्यांकन के 30 फीसद एवं बोर्ड परीक्षा के 40 फीसद जिससे बोर्ड की परीक्षा एक घंटे के समय में हो सकती है। इस वर्ष भी कक्षा 1 से 11 तक परीक्षा नहीं हुई है परंतु मूल्यांकन तो विद्यालय के द्वारा किया जा सकता है। हमारे देश में कुछ दशकों की शिक्षा व्यवस्था के कारण तीन घंटे की परीक्षा ही शिक्षा का एक मात्र आधार बन गई है। जब परीक्षा नहीं होती है तब छात्र, शिक्षक, अभिभावक सब शांत बैठ जाते हैं। जब सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया चलेगी तो यह सभी लोग छात्र की पढ़ाई की चिंता करेंगे जिससे छात्र शैक्षिक दृष्टि से कहां खड़ा है उसका मूल्यांकन भी हो जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ई-लर्निंग व ऑनलाइन शिक्षा पर काफी बल दिया गया है। इस विकल्प पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अन्यथा हमारे देश में नीतियों में तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, परंतु क्रियान्वयन की दृष्टि से धरातल पर बहुत कुछ नहीं हो पाता है। जब ऑनलाइन की बात आती है तब 'डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर' का प्रश्न उठता है।

यह वास्तविकता भी है परंतु इसका समाधान किया जा सकता है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ कंपनियों का कहना है कि वह इस समस्या का समाधान दे सकते हैं।

ऑनलाइन परीक्षा में जिस क्षेत्र में कनेक्टिविटी की समस्या है या छात्रों के पास लैपटॉप, मोबाइल आदि की उपलब्धता नहीं है वहां परीक्षा केंद्रों पर जाकर छात्र परीक्षा दे सकते हैं। रेलवे, बैंकिंग आदि परीक्षाएं इसी प्रकार की जा रही है। विगत वर्ष जेईई मेन परीक्षा एनटीए के माध्यम से इसी प्रकार आयोजित की थी जिसमें छह लाख से अधिक छात्र सहभागी हुए थे। शिक्षा नीति में भविष्य में बोर्ड परीक्षाएं एनटीए के द्वारा आयोजित करने हेतु प्रस्ताव रखा है जो संभवतः ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। परीक्षाएं सुरक्षित एवं शुचितापूर्ण हों, इस हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर एवं एप आदि विकसित करने होंगे। सरकारों को इस हेतु अतिशीघ्रता से कदम उठाने होंगे।

संपादकीय

उदास है गंगा और खामोश हिमालय

क्रूर कोरोना ने प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता और कई सामाजिक आंदोलनों के सूत्रधार सुंदरलाल बहुगुणा को हमसे छीन लिया। हिमालय और गंगा के लिए चलाई गई मुहिम के जरिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले बहुगुणा पर्यावरण को एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए सदैव याद किए जाएंगे। वह एक ऐसे समय में हमसे विदा हुए, जब भोगवादी जीवन शैली व विकास के नाम पर प्रकृति के मर्दन से उत्पन्न महामारी और गंगा में शवों के तैरने जैसी अभूतपूर्व चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। तत्कालीन टिहरी रियासत के एक राजशाही समर्थक परिवार में पैदा हुए बहुगुणा की शिक्षा-दीक्षा उस समय के नामी संस्थानों में हुई थी। वह चाहते, तो उस वक्त टिहरी रियासत में किसी बड़े पद पर तैनात हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सुविधाजनक रास्ता चुनने के बजाय शोषित-पीड़ित जनता का साथ देने की राह चुनी। टिहरी रियासत के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह करने वाले श्रीदेव सुमन से प्रेरणा लेकर उन्होंने टिहरी को राजशाही से मुक्त करने के आंदोलन में खुद को समर्पित कर दिया। बहुगुणा ने कई बार राजशाही की हिंसा झेली, दमन झेला, लेकिन जनपरस्ती का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ देश में स्वतंत्रता आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ ही जब टिहरी में राजशाही के विरुद्ध आक्रोश बढ़ने लगा, तब बहुगुणा इस मुहिम के अगुआ दस्ते में शामिल हो गए। राजशाही के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रजामंडल के वह अग्रणी नेताओं में शामिल रहे और देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए जुटी कांग्रेस के सचिव भी रहे। लेकिन आजादी के बाद 1956 में बहुगुणा की जीवन-दिशा बदल गई, और इसमें उनकी पत्नी विमला बहुगुणा का बड़ा योगदान रहा। सर्वोदय कार्यकर्ता सरला बहन की शिष्या विमला बहुगुणा ने उनके सामने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद वह राजनीति छोड़ेंगे, सिर्फ समाज सेवा करेंगे। इस शर्त ने बहुगुणा का जीवन-दर्शन तो बदला ही, उत्तराखंड में आजादी के बाद के शुरुआती जनांदोलनों का उन्हें अगुआ भी बना दिया। बहुगुणा ने जैसे ही सक्रिय राजनीति छोड़कर सामाजिक आंदोलन शुरू किए, पूरे सामाजिक परिवेश में हलचल पैदा हो गई। उन्होंने उस दौर में समाज के हाशिये के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए छुआछूत विरोधी, दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने जैसे आंदोलन शुरू किए। इन आंदोलनों में भारी विरोध झेलने के बावजूद बहुगुणा अडिग रहे। इसके बाद उन्होंने नशे के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसके लिए भी उन्हें खूब विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह आंदोलन गढ़वाल से कुमाऊं तक फैला और अंततः सरकार को पूरे उत्तराखंड को नशामुक्त क्षेत्र घोषित करना पड़ा। हालांकि, 'सिस्टम' ने पहाड़ पर नशा के जारी रखने के दूसरे रास्ते निकाल लिए। धर्मग्रंथों में हिमालय की महिमा नई बात नहीं है। पर बहुगुणा ने देश-दुनिया को ऑक्सीजन, जल-भंडार व पर्यावरण-सुरक्षा में हिमालय के योगदान का महत्व दिलाने में अहम योगदान दिया। इस मुहिम में वह केवल आज के उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक पदयात्रा की, जिसने पूरे हिमालयी समाज को जोड़ने और उनकी पर्यावरणीय चिंताओं को एक-दूसरे से साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेपाल और भूटान में भी पदयात्राएं करके बहुगुणा ने हिमालयी समाज की चिंताओं को एक-दूसरे तक पहुंचाया। वह सबसे अधिक चर्चा में तब आए, जब उन्होंने टिहरी में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बन रहे टिहरी बांध का विरोध शुरू किया। हालांकि बहुगुणा के शामिल होने के पहले आंदोलन शुरू हो चुका था, मगर इसे देश-दुनिया में ख्याति बहुगुणा के शामिल होने के बाद मिली। उन्होंने इस आंदोलन के जरिए न केवल गंगा को बचाने की मुहिम को सामाजिक-राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए राजनीति को मजबूर किया, बल्कि बड़े बांधों के विनाशकारी प्रभाव के प्रति पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। बहुगुणा के आलोचक भले यह कहें कि वह टिहरी की लड़ाई जीत नहीं सके, लेकिन यह उनके ही संघर्ष का प्रतिफल है कि टिहरी में पुनर्वास के सवाल को संजीदगी से निपटाने के लिए सरकारें मजबूर हुई और दुनिया भर में बड़े नदी-बांधों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के खिलाफ जनमत तैयार होने लगा। बहुगुणा बार-बार यह कहते रहे, 'शासक याद रखें, हिमालय पानी के लिए है, 'रेवेन्यू' के लिए नहीं'। हम हिमालय वासी विकास के नाम पर की जा रही आत्मघाती गतिविधियों से काफी त्रस्त हैं। हिमालय के लिए एक दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। प्रकृति के वरदान गंगा को मरते हुए नहीं देख सकता।' वह यह भी कहते कि मुद्दा विकास बनाम पर्यावरण का नहीं है। यह तो अस्तित्व की लड़ाई है। इन मुद्दों को लेकर वह टिहरी बांध के कोने में एक छोटी सी कुटिया बना वर्षों सत्याग्रह, अनशन करते रहे। लेकिन सरकारों ने उनकी नहीं सुनी या फिर उन्होंने जो वादे उनसे किए, उन्हें पूरा नहीं किया। इसके बावजूद बहुगुणा विचलित नहीं हुए। वही कहते रहे, जब सरकारें इस स्तर पर आपका विरोध करें, तो यह आपके आंदोलन की सफलता है। बहुगुणा का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने अपने जीवनकाल में उत्तराखंड की युवा पीढ़ी को अपने समाज, पर्यावरण को दुरुस्त करने की चिंताओं से लैस किया। सन 1974 में अस्कोट-आराकोट जैसी सुदूर पश्चिम नेपाल से हिमाचल की सीमा तक पदयात्रा हो या टिहरी में हेंवल घाटी में बीज बचाओ आंदोलन, बहुगुणा की प्रेरणा इनमें अहम रही। वह हर बैठक में अपने पिट्ठू में अखरोट के पौधे लेकर आते और कहते, अपने गांव में लगाना, यही पहाड़ के स्वावलंबन का आधार बनेगा। बहुगुणा मानते थे कि यदि उत्तराखंड से बहने वाली नदियों का पानी हर चोटी तक पहुंचा दिया जाए, तो यह राज्य आत्मनिर्भर हो जाएगा। वह प्रकृति पर आधारित स्वावलंबी जीवन के बड़े पैरोकार थे और ताउम्र अपने इस दर्शन पर अडिग रहे। सुंदरलाल बहुगुणा के जाने से उत्तराखंड, देश और दुनिया की उस पीढ़ी का सबसे अधिक नुकसान होने वाला है, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के साथ अपनी अगली पीढ़ियों के सुखद भविष्य का सपना देखती है। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होनी चाहिए कि हम प्रकृति का अविवेकी दोहन बंद करें और अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन जीने के प्रयास करें, ताकि प्रकृति हमें हर संकट से बचाने में ढाल बन जाए।

प्रवीण कुमार सिंह

क्या टूलकिट संवाद-संचार का एक अहम औजार या इसकी कोई सार्थकता-उपयोगिता भी है

> लेकिन इंटरनेट मीडिया के प्रादुर्भाव ने यह कंट्रोल खत्म कर दिया है। हालांकि इसका सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि जिस सूचना को सत्ता-प्रशासन दबाना चाहता है, वह भी फौरन जनता तक पहुंच जाती है। सूचना के इस लोकतांत्रिकरण की वजह से हालत यह हो गई है कि आज के दौर में बहुतेरे टीवी चैनल सरकार के पैरोकार के रूप में कुख्यात हो गए हैं और जनता में एक बड़ा वर्ग उन चैनलों की बजाय इंटरनेट मीडिया पर आई सूचनाओं में ज्यादा यकीन करने लगा है। पर इस दौर में भी अखबारों की सत्यता और विश्वसनीयता उस तरह खंडित नहीं हुई, जैसा टीवी न्यूज चैनलों के संबंध में हुआ है।

इंटरनेट मीडिया के बढ़ते प्रभाव के दौर में इसकी संतुलित, तटस्थ और निष्पक्ष भूमिका के आदर्शों के तहत टूलकिट की उन कसौटियों पर जांच करना आज जरूरी हो गया है, जो इसे पूर्वाग्रहों और निहित स्वार्थों से अलग साबित कर सकें और इसके भविष्य के बारे में कोई मानक राय बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। टूलकिट की चर्चा का हालिया प्रकरण सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेता संबित पात्रा के एक ट्वीट से जुड़ा है, जिसे ट्विटर ने हाल में 'मैनिपुलेटेड मीडिया' यानी गुमराह करने वाली पोस्ट करार दिया है। मैनिपुलेटेड मीडिया का अभिप्राय ऐसी तस्वीरों, वीडियो या स्क्रीनशॉट्स से है जिनके बल पर किए जाने वाले दावों की सत्यता पर संदेह हो और माना जाए कि उनके मूल स्वरूप को संपादित करते हुए उनसे छेड़छाड़ की गई है और उनमें मनमुताबिक बदलाव किया गया हो। भाजपा के नेता संबित पात्रा ने अपने इन ट्वीट्स में दावा किया था कि यह कांग्रेस का टूलकिट है। 18 मई को संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया था, उसमें कांग्रेस का लेटरहेड दिखाते हुए दावा किया कि उसमें यह बताया गया था कि इंटरनेट मीडिया पर किस तरह ट्वीट और जानकारी साझा करनी है। संबित पात्रा ने कुछ दस्तावेज और तस्वीरें आदि दिखाते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि यह पार्टी एक कथित टूलकिट के सहारे इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने का काम कर रही है। उसमें 'सुपर स्प्रेडर कुंभ' और कोरोना वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए 'मोदी वैरिएंट' जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। साथ ही मोदी सरकार को कठघरे में लाने के लिए विदेशी मीडिया की मदद लेने, भारत में शवों और जलती चिताओं आदि की तस्वीर उपलब्ध कराने में उनकी मदद करने, कुंभ के आयोजन को भारतीय जनता पार्टी के हिंदू एजेंडा से जोड़ने, कोरोना काल में राजनीतिक लाभ उठाने की बात कही गई है।

इंटरनेट मीडिया और टीवी चैनलों के जरिये संबित पात्रा ने ऐसे कई सबूत पेश किए जिनमें दावा किया गया कि यह देशविरोधी टूलकिट कांग्रेस रिसर्च विंग से जुड़ी और पार्टी के शीर्ष नेताओं की करीबी सौम्या वर्मा ने तैयार की थी। संबित ने राहुल गांधी के साथ फोटो में खड़ी सौम्या की तस्वीर भी जारी की। जैसा कि स्वाभाविक था, कांग्रेस ने ऐसी कोई टूलकिट तैयार करने से साफ इन्कार किया है। यही नहीं, मामला उजागर होने के बाद सौम्या वर्मा ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिए। भले ही कांग्रेस ने खुद को इस मामले से अलग करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की इंटरनेट मीडिया टीम की सदस्य संयुक्ता बासु का एक ट्वीट इसमें पार्टी की संलिप्तता का संकेत करता है। इसमें संयुक्ता ने टूलकिट को सही ठहराया है और लिखा है कि विरोधी की छवि को ध्वस्त करना विपक्ष का काम है और कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। यह मामला कई वजहों से बेहद बड़ा हो गया है। खास तौर से जिस तरह से ट्विटर ने पात्रा के ट्वीट को टैग किया , उससे केंद्र सरकार ने अपनी असहमति प्रकट की। सरकार ने कहा कि ट्विटर की भूमिका मीडिया के एक माध्यम की है, जबकि इस पर एक्शन लेकर उसने एक फैसला देने की कोशिश की है, जो गलत है। सरकार ने यह भी साफ किया कि ट्विटर की ओर से ऐसी टैगिंग उसके पूर्वाग्रह को दर्शाती है और यह समानता व पक्षपात के मूल्यों का उल्लंघन है। यही नहीं, इस मामले में कानूनी एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। इसी क्रम में 24 मई को ट्विटर की भारतीय इकाई को इस संबंध में एक नोटिस भेजा गया। इसी दिन दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुड़गांव स्थित दफ्तरों में पहुंचकर अपने हाथों से नोटिस थमाया। इस बीच टूलकिट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक चुका है। सर्वोच्च अदालत में दाखिल एक याचिका में कहा गया है कि टूलकिट मामले में कांग्रेस पर जो आरोप लगाया गया है उसकी जांच की जाए। अगर जांच में पाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त है तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कांग्रेस, केंद्र और चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है।

टूलकिट से जुड़ा मौजूदा प्रसंग निश्चय ही काफी चर्चा में आ गया है, लेकिन इससे जुड़ा एक बड़ा किस्सा इस साल की शुरुआत में घटित हो चुका है। दरअसल कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान फरवरी में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता किशोरी ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर एक टूलकिट साझा करते हुए लिखा था कि अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूलकिट की मदद ले सकते हैं। यह टूलकिट सामने आई तो इससे जुड़े कई मामलों का पर्दाफाश भी हुआ। जैसे यह पता चला कि इसे बनाने और प्रसारित करने में मुख्य भूमिका भारत की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की है। यह जानकारी भी सामने आई कि इसके निर्माण में खालिस्तान समर्थक संगठन उस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का भी हाथ है, जिसके सह-संस्थापक धालीवाल कनाडा के वैंकूवर में रहते हैं। इन जानकारियों के सामने आने पर भाजपा ने दावा किया कि किसानों के आंदोलन के पक्ष में जारी की गई टूलकिट से खालिस्तान समर्थकों का जुड़ाव साबित करता है कि यह आंदोलन एक प्रायोजित कार्यक्रम है और भारत को तोड़ने वाले खालिस्तान समर्थक इस आंदोलन का हिस्सा हैं। हालांकि इस मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें यह कहते हुए तिहाड़ से रिहा करवाया कि इंटरनेट मीडिया पर एक वाट्सएप ग्रुप बनाना और कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की नीयत से बनाई गई टूलकिट का संपादक होना कोई जुर्म नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इस टूलकिट को 'लोगों में विद्रोह पैदा करने वाले दस्तावेज' के रूप में दर्ज किया था और इसी आधार पर अपनी जांच के दायरे में लिया था।

इसमें संदेह नहीं है कि जब से देश और दुनिया में इंटरनेट मीडिया के विभिन्न मंचों का इस्तेमाल बढ़ा है, उस पर कही-सुनी-लिखी और दिखाई जाने वाली बातों के नियमन का मसला काफी पीछे छूट गया है। फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, इंस्टाग्राम के दौर से पहले की दुनिया में सूचनाएं और जानकारी पहुंचाने के रूप में जो मीडिया सक्रिय थे, उन पर सूचनाओं के प्रवाह और नियंत्रण की कमान इसके यानी मीडिया के जानकारों के हाथ में थी। ऐसे में आम जनता तक पहुंचने वाली कोई भी सूचना संपादन के काफी सख्त नियम-कायदों के चरणों से होकर गुजरती थी। लेकिन इंटरनेट मीडिया के प्रादुर्भाव ने यह कंट्रोल खत्म कर दिया है। हालांकि इसका सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि जिस सूचना को सत्ता-प्रशासन दबाना चाहता है, वह भी फौरन जनता तक पहुंच जाती है। सूचना के इस लोकतांत्रिकरण की वजह से हालत यह हो गई है कि आज के दौर में बहुतेरे टीवी चैनल सरकार के पैरोकार के रूप में कुख्यात हो गए हैं और जनता में एक बड़ा वर्ग उन चैनलों की बजाय इंटरनेट मीडिया पर आई सूचनाओं में ज्यादा यकीन करने लगा है। पर इस दौर में भी अखबारों की सत्यता और विश्वसनीयता उस तरह खंडित नहीं हुई, जैसा टीवी न्यूज चैनलों के संबंध में हुआ है। पर यहां प्रश्न है कि क्या इंटरनेट मीडिया के संचालकों को उसी तरह किसी तथ्य या सूचना पर अपना फैसला थोपने या राय बनाने का हक मिलना चाहिए, जैसा अधिकार अखबार या टीवी न्यूज चैनलों के संपादकों को होता है।

बंदा दफ्तर में निकम्मा हो, पर जुगाड़ सही हो तो घोषित हो सकता है कोरोना योद्धा

एक शोध-सर्वे से साफ हुआ कि कोरोना की हाल की लहर में जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उन्हें हजारों करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। अस्पताल जाने वाले हर परिवार ने औसतन डेढ़ लाख रुपये खर्च किए हैं। अस्पताल, चिकित्सा के बिजनेस चकाचक हो गए हैं। तमाम तरह के टेस्ट करने वाली एक पैथोलॉजी लैब के शेयर के भाव एक साल में करीब 78 प्रतिशत उछल गए हैं। अब और कितनी कमाई हो कोरोना, डाइबिटीज आदि के टेस्टों से। जिंदगी बड़े इम्तिहान लेती है और समय-समय पर टेस्ट भी लेती रहती है। ये टेस्ट-वे टेस्ट। तमाम तरह के मेडिकल टेस्टों समेत। दूर-दराज के एक सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एक डॉक्टर मित्र नाराज होकर बता रहे थे कि उनके यहां तो नॉर्मल टाइम में भी काम न होता। मतलब नेचुलर निकम्मापन है। उनका आशय यह था कि दूर-दराज के स्वास्थ्य केंद्रों के निकम्मेपन पर मीडिया की नाराजगी ठीक नहीं है। उस निकम्मेपन को सहज भाव ले लिया जाना चाहिए।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरा मित्र काम करता है, बहुत कम काम करता है, पर कविता करता है और करीब 36 काव्य संस्थाओं से वह कोरोना योद्धा होने का सर्टिफिकेट ले आया है। बंदा दफ्तर में निकम्मा हो, पर जुगाड़ सही हो तो कोरोना योद्धा घोषित हो सकता है। कोरोना ने जाने क्या-क्या दिखाया है? एक राज्य से समाचार आया कि वहां बंदों को नकली रेमडेसिविर सप्लाई की गई, फिर भी वहां लोग स्वस्थ हो गए। लोग नीम का काढ़ा पीकर स्वस्थ हो रहे हैं, नकली रेमडेसिविर लेकर स्वस्थ हो रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि एक प्रयोग और संभव है-कोरोना के मरीजों को उनके घर वालों से, पड़ोसियों से गालियां दिलवाई जाएं कि लापरवाह है, बिना मास्क के घूमता है। बहुत संभव है कि इतने या उतने प्रतिशत मरीज गाली खाकर भी ठीक हो जाएं। फिर झुनझुनपुरा मेडिकल रिसर्च जर्नल छाप सकता है कि भारत में मरीज गाली खाकर भी ठीक हो रहे हैं। ये-ये गालियां खाकर ठीक हुए। फिर इन गालियों के वाचन की सीडी, वीडियो बन जाएंगे और हर घर से गालियां सुनाई देने लग जाएंगी। गालियों की जैसी वैराइटी है यहां, वैसी शायद ही किसी ओर देश में हो। अवध की गालियां अलग, ब्रज की गालियां अलग, बुंदेलखंड की गालियां अलग। गाली ही गाली, खा तो लें। देश मेरा रंगरेज है बाबू, घाट-घाट यहां घटता जादू।.

कोरोना ने कैसे-कैसे धंधे पेश कर दिए हैं। कोरोना में गए बंदे के साथ उसके घरवाले तक खड़े होने में कतराते हैं। ऐसे में कइयों ने धंधे खड़े कर लिए। तीस हजार दीजिए, जाने वाले को सम्मान के साथ विदा करवा देंगे। थोड़े ज्यादा पैसे दीजिए तो जाने वाले को महान बता ही न देंगे, बल्कि साबित भी कर देंगे। हर चीज का पैकेज है। आप तो बस रकम ले कर आ जाओ। कोरोना की खबर फैली ही थी कि एक मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव का फोन आ गया। बोला, परेशान न होइए, आपका इंतजाम हम कर देंगे। यहां इतनी रकम ट्रांसफर कर दीजिए, आपके जाने के बाद हम आपको सबसे बड़ा लेखक घोषित करवा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस निकल लीजिए आराम से। बाकी तो हम हैं न। मैंने उसे बताया, देखिए, माइल्ड टाइप का कोरोना है, फिट हो जाऊंगा। फिर भी मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव ने जोर दिया, आप चिंता न करें, कोरोना से नहीं गए तो भी हम आपको महान घोषित करवा देंगे। हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी को भी महान घोषित कराने का। आपके ही पड़ोसी विकट भ्रष्ट अफसर को जाने के बाद हमने मानवीय संवेदनाओं से परिपूरित इंसान जैसा कुछ घोषित कराया है। आप तो बस निकल लो, आपको महान घोषित करवाना हमारा जिम्मा। मैंने कहा अभी जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव निराश टाइप हो गया।

कोरोना ने इंगलिश अध्यापन के सामने नई चुनौतियां पेश कर दी हैं। इंगलिश के अध्यापक बच्चों से पूछ रहे हैं कि रेमडेसिविर की स्पेलिंग बताओ, टोसिलिजुमाब की स्पेलिंग बताओ। जो बच्चे इनकी स्पेलिंग न बता पाएं, उन्हें कोरोना इंगलिश निगेटिव घोषित किया जाए। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब से पीछा छूटने वाला नहीं है।

बड़ी आर्थिक चुनौती

कोरोना के असर से अर्थव्यवस्था के जिस तेजी से उबरने की उम्मीद थी, दूसरी लहर ने उस पर पानी फेर दिया है। वित्त वर्ष 2022 में पहले जहां देश की ग्रोथ 11-14 फीसदी रहने का अनुमान लगाया जा रहा था, अब उसे घटाकर 8.5-10 फीसदी कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2021 में ग्रोथ माइनस 7.3 फीसदी रही। कोरोना महामारी की पहली लहर में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा असर नहीं हुआ था और वहां की इकॉनमी मजबूत बनी हुई थी। दूसरी लहर में गांवों पर इसका व्यापक असर हुआ है, जिससे खपत में कमी आने की आशंका है। मई में लॉकडाउन के कारण जहां कंपनियों के प्रॉडक्शन और दुकानों से बिक्री प्रभावित हुई, वहीं लोगों ने अनिश्चितता के कारण खर्च घटाया। इसलिए मई में अप्रैल की तुलना में टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बिक्री में 65 फीसदी, स्मार्टफोन की बिक्री में 30 फीसदी की कमी आई। अप्रैल में जहां कंपनियों ने शोरूम में 2 लाख 86 हजार पैसेंजर गाड़ियां भेजी थीं, वहीं मई में इनकी संख्या घटकर 1 लाख से कुछ अधिक रह गई। प्रॉडक्शन और खपत में कमी का रोजगार पर भी बुरा असर हुआ है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) का दावा है कि मई महीने में 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और 30 मई को खत्म सप्ताह में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 18 फीसदी के साथ पिछले एक साल में सबसे अधिक हो गई। जून में कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी गई है, इसलिए हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन महामारी के पहले के स्तर तक पहुंचने में अर्थव्यवस्था को वक्त लगेगा। यहां यह बात भी याद रखनी चाहिए कि पिछले साल महामारी के आने से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी हुई थी। महामारी ने इस मोर्चे पर दिक्कत बढ़ा दी है और समाज के सभी वर्गों पर इसका असर पड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले प्यू रिसर्च का एक सर्वे आया, जिसमें बताया गया कि 2020 में भारत में मध्यवर्गीय लोगों की संख्या में 3.5 करोड़ की कमी आई।

इसी तरह से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल 23 करोड़ लोग गरीबी की दलदल में फंस गए। सरकार ने पिछले साल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बड़ा राहत पैकेज दिया था। सरकारी खजाने की हालत ठीक नहीं, इसलिए अभी उसके लिए ऐसा करना मुश्किल है। इसलिए उदय कोटक जैसे उद्योगपतियों ने कहा है कि रिजर्व बैंक अधिक नोट छापे और सरकार अपनी बैलेंट शीट बढ़ाए। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से मौजूदा आर्थिक मुश्किलों से कैसे निपटा जाएगा, इसके संकेत नहीं मिले हैं। यह बात भी तय है कि जब तक लोगों के हाथ में खर्च करने लायक पैसा नहीं बढ़ेगा, तब तक खपत बढ़ने की उम्मीद नहीं है।

एक राज्य में सजा की दर 85 फीसद है तो अन्य राज्य में सौ आरोपितों में से सिर्फ छह सजा पाते हैं

> यदि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय बदलने को तैयार नहीं हो तो इस संबंध में संसद को कानून बनाना चाहिए। इसके साथ हमें अपने संबंधित कानूनों की प्राचीनता के बारे में भी पुनर्विचार करना होगा। यदि तमाम लोग न्याय के लिए अब भी कराह रहे हैं तो इसके लिए हमारे कानूनों की प्राचीनता भी जिम्मेदार है, जो अब उतने कारगर नहीं रहे। देखा जाए तो 1860 में भारतीय दंड संहिता बनी और 1949 में पुलिस एक्ट। इसी तरह 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना और 1908 में सिविल प्रक्रिया संहिता। आज की कानूनी समस्याओं को देखते हुए इन कानूनों में जरूरी फेरबदल भी किए जाने चाहिए।

पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने 1999 में घटित सेनारी नरसंहार के सभी दोषियों को सजा से मुक्त कर दिया। उसके अनुसार, 'अभियोजन पक्ष इस कांड के आरोपितों पर लगे आरोपों को साबित करने में सफल नहीं हो सका। वह कोई ठोस सुबूत भी सामने नहीं ला पाया।' ज्ञात हो कि बिहार के जहानाबाद जिले के सेनारी गांव के इस नृशंस कांड में 34 लोगों की गला काटकर और पेट फाड़कर हत्या कर दी गई थी। इस कांड से पूरा देश हिल गया था। इस मामले में निचली अदालत ने तो दस लोगों को फांसी और तीन को उम्रकैद की सजा दी थी, पर अब हाई कोर्ट में वह सजा उलट गई है। खबर है कि बिहार सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। वहां क्या होता है, कुछ कहना कठिन है।

वैसे यह इकलौता ऐसा मामला नहीं है, जिसमें किसी गंभीर अपराध के आरोपित अदालत द्वारा दोषमुक्त करार दिए गए हों। इससे पहले बिहार के ही लक्ष्मणपुर बाथे में 1997 में एक साथ 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी 2013 में पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को बदलते हुए सभी दोषियों को बरी कर दिया था। बिहार के साथ-साथ देश के अन्य प्रांतों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, बल्कि यह कहना उपयुक्त होगा कि आते ही रहते हैं। पूरे देश की अपराध की घटनाओं पर एक नजर दौड़ाने पर यह लगता है कि कई बार अभियोजन पक्ष की कमजोरी के कारण ऐसे भी आरोपित बरी हो जाते है, जिनके बारे में यह आम धारणा रहती है कि वे अपराधी हैं।

ऐसे नरसंहारों, जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया

था, के आरोपितों की दोषमुक्ति चिंताजनक परिघटना है। जब ऐसा होता है तो लोगों का विधि के शासन पर से भरोसा डिगता है। शांतिप्रिय आम लोगों के लिए भी और खुद देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए भी यह चिंता का विषय बनना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है? वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'दोषमुक्ति का हरेक मामला न्याय व्यवस्था की विफलता है। राज्यों को चाहिए कि वे छह माह के भीतर ऐसी कार्य प्रणाली विकसित करें, ताकि न तो कोई निर्दोष दंडित हो और न ही कोई दोषी बच न पाए। राज्य सरकारें इस बात की भी समीक्षा करें कि दोषमुक्ति के कारण क्या-क्या हैं। यह भी देखें कि अनुसंधान और अभियोजन में क्या कमी या दोष रह जाता है। उसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए।' लगता है कि इस दिशा में कुछ नहीं हुआ।

बिहार सहित देश के कुछ राज्यों में अदालतों से दोषमुक्ति का प्रतिशत बहुत अधिक है, पर यदि बड़े-बड़े नरसंहारों में भी एक-एक करके आरोपित दोषमुक्त होते चले जाएं तो शासन के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए। हालांकि देश में न्याय प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए समय-समय पर न्यायविदों और आयोगों के सुझाव आते रहते हैं, लेकिन उन पर इस तरह अमल नहीं होता, जिससे स्थिति में नजर आने लायक सुधार हो। यह गंभीर चिंता की बात है कि किसी-किसी राज्य में सजा की दर सिर्फ छह प्रतिशत है। आखिर इस स्थिति को तत्काल सुधारने के लिए विशेष उपाय क्यों नहीं किए जाते? कोविड महामारी के गुजर जाने के बाद पूरे देश के हुक्मरानों को इस बात पर अवश्य ही विचार करना चाहिए कि एक राज्य में तो सजा की दर 85 प्रतिशत है तो एक अन्य राज्य में सौ आरोपितों में से सिर्फ छह ही सजा क्यों पाते हैं? यह आंकड़ा सिर्फ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) के तहत दायर मुकदमों से संबंधित है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संतोष हेगड़े ने कहा था कि जब तक हम अपने न्याय शास्त्र में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम आपराधिक न्याय प्रणाली में संतोषप्रद सुधार नहीं कर पाएंगे।

मौजूदा न्याय शास्त्र के अनुसार, 'भले 99 आरोपित छूट जाएं, किंतु किसी एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए।' जस्टिस हेगड़े की राय थी कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए हमें इसे उलट देना चाहिए, ताकि एक भी आरोपित न छूटे। आपराधिक न्याय प्रणाली की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए हमें जस्टिस हेगड़े की इस सलाह पर विचार करना ही चाहिए, अन्यथा देर-बहुत देर हो जाएगी। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुका है कि कोई भी आरोपित दोषमुक्त होता है तो उससे लोगों को यह नतीजा निकालने का अवसर मिल जाता है कि दोषमुक्ति से पहले उसे नाहक परेशान किया गया। क्या यह धारणा इस देश की न्याय प्रक्रिया के स्वास्थ्य के लिए ठीक है?

जाहिर है देश में आपराधिक न्याय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। शुरुआत नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलिग्राफिक टेस्ट से हो सकती है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आरोपित या फिर संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही उसका नार्को टेस्ट हो सकता है। किसी की इच्छा के खिलाफ उसका ब्रेन मैपिंग नहीं हो सकता। पॉलिग्राफ टेस्ट के बारे में भी यही बात लागू होगी। हालांकि कुछ मामलों में संबंधित अदालत के आदेश से ऐसे टेस्ट आज भी होते हैं, किंतु यदि इसकी छूट जांच में लगे आम पुलिस अफसरों को भी रहती तो इस देश में सजा का प्रतिशत बहुत बढ़ सकता था। ऐसे में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश करना चाहिए कि समय की जरूरत को देखते हुए वह अपने उस निर्णय को बदले, क्योंकि इसका लाभ आरोपितों को मिल रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय बदलने को तैयार नहीं हो तो इस संबंध में संसद को कानून बनाना चाहिए।

इसके साथ हमें अपने संबंधित कानूनों की प्राचीनता के बारे में भी पुनर्विचार करना होगा। यदि तमाम लोग न्याय के लिए अब भी कराह रहे हैं तो इसके लिए हमारे कानूनों की प्राचीनता भी जिम्मेदार है, जो अब उतने कारगर नहीं रहे। देखा जाए तो 1860 में भारतीय दंड संहिता बनी और 1949 में पुलिस एक्ट। इसी तरह 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना और 1908 में सिविल प्रक्रिया संहिता। आज की कानूनी समस्याओं को देखते हुए इन कानूनों में जरूरी फेरबदल भी किए जाने चाहिए।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

यूपीपीएससी में कामकाज ने पकड़ी रफ्तार, अब विभिन्न भर्तियों के चयनितों को शीघ्र मिलेगी नियुक्ति

प्रयागराज । कोरोना का प्रभाव कम होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की गतिविधि तेज हो गई है। नई भर्ती निकालने के साथ चयनितों को नियुक्ति देने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मौजूदा समय में दर्जनभर से अधिक भर्ती परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन करने के साथ संबंधित विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। जुलाई-अगस्त महीने तक चयनितों को नियुक्ति दिलाने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अप्रैल से जून तक की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। कार्यालय का काम भी सुस्त चल रहा था। इधर, स्थिति सामान्य होने पर चयनितों को नियुक्ति देने का काम जोर-शोर से चल रहा है। आरओ/एआरओ-2016 के चयनितों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन की तारीख घोषित हो चुकी है। वहीं, पीसीएस-2020, एसीएफ/आरएफओ यानी सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी-2020 के 12, डायट प्रवक्ता के 45, एलटी ग्रेड-2018 के तहत हिंदी के 1400 व सामाजिक विज्ञान विषय के 1851, प्रवक्ता राजकीय इंटर कालेज के 17, आरओ/एआरओ-2016 के 260, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता कंप्यूटर के चयनितों को नियुक्ति देने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर प्रतियोगी काफी दिन से इंटरनेट मीडिया में अभियान चला रहे थे। प्रतियोगी चयनितों को शीघ्र नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। इसके मद्देनजर आयोग ने उस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

इसी साल परीक्षा कराने की योजना – उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2021 के कैलेंडर में प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं को इसी साल कराने की योजना बनाई है। आयोग का मानना है कि परीक्षाएं आगे बढ़ाने से आने वाले दिनों में स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी। तारीख आगे-पीछे करके उसे पूरा कराया जाएगा, लेकिन 2022 के लिए कोई परीक्षा नहीं टाली जाएगी।

बिहार में लॉकडाउन समाप्त, अनलॉक- 1 की छूटों के तहत दुकान खोलने का समय बढ़ा, वाहन भी चलेंगे

पटना । बिहार में मंगलवार को लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त हो रहा है। इसके साथ लॉकडाउन भी समाप्त हो रहा है। बुधवार से राज्य सरकार अनलॉक का पहला चरण आरंभ हो रहा है। इस पर आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला किया गया। कोरोनावायरस के लगातार घट रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक- 1 में कई तरह की छूटें दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। राज्य सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखते हुए आम जन-जीवन को पटरी पर लाई जाए।

कल से प्रभावी हो जाएंगे अनलॉक के प्रावधान- कल से अनलॉक के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे। इसके तहत दुकानों के खोलने का समय शाम पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। आज तक दुकानें अपराह्न दो बजे तक ही खुल रहीं हैं। नाईट कर्फ्यू भी शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। दिन में गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी। इसके साथ निजी कार्यालय भी 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। अभी तक वर्क फ्रॉम होम की ही अनुमति थी। सरकारी कार्यालयों में भी 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है।

आज रात में समाप्त हो जाएगा लॉकडाउन- 4- पांच से 15 मई तक लॉकडाउन- 1, 16 से 25 मई तक लॉकडाउन- 2 तथा 26 मई से एक जून तक लॉकडाउन- 3 लागू रहे थे। लाकडाउन- 4 बीते दो जून से आरंभ होकर आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के पहले जिलाधिकारियों से कोरोना संक्रमण के हालात का फीडबैक लिया था। इसमें जिलाधिकारियों ने संक्रमण पर नियंत्रण रखते हुए रियायतें देने की बात कही थी। मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से आपदा प्रबंधन समूह की बैठक लॉकडाउन को लेकर बैठक बुलाई गई। इसमें राज्य के मुख्य सचिव व विकास आयुक्त के साथ गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी और राज्य के पुलिस महानिदेशक शामिल रहे। बैठक में जिलों से मिले फीडबैक पर विमर्श के बाद छूट के साथ अनलॉक का फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री ने की लॉकडाउन समाप्त होने की घोषणा- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लॉकडाउन के समाप्त करने की घोषणा करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि अब छूटों के साथ अनलॉक के प्रावधान प्रभावी रहेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने में लॉकडाउन काफी प्रभावी रहा है। ऐसे में सरकार धीरे-धीरे छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। पांच मई को जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब राज्य में हर दिन कोरोना के करीब 15 हजार मामले सामने आ रहे थे, जो धीरे-धीरे घटते हुए अब करीब एक हजार तक आ गए हैं। अचानक पूरी तरह अनलॉक से लोगों के लापरवाह होने की आशंका है, जिससे संक्रमण दर फिर बढ़ सकती है।

पति की सब्जी में नींद की गोली डाल पत्नी ने घोंट दिया गला, फिर खुलेआम पटना के प्रेमी के साथ लगी घूमने

अरवल । बिहार के जहानाबाद में प्रेमी के चक्कर में पड़कर पत्नी ने पति की ही जान ले ली। नगर थाना क्षेत्र के विरन बिगहा गांव के गौरैया स्थान के समीप एक जनवरी को छोटन सिंह का शव बरामद किया गया था। घटना के बाद भाई द्वारा हत्या का कारण भूमि विवाद बताते हुए छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लेकिन पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो इसमें हत्या के दूसरे कारण सामने आने लगे। सोमवार को पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने इस हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए बताया कि नामजद अभियुक्तों की संलिप्ता इस घटना में सामने नहीं आ रही है। घटना का कारण भूमि विवाद के बजाय प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। एसपी ने बताया कि मृतक की पत्नी राजमुनी देवी ने अपने एक दोस्त मोनू कुमार उर्फ मनु उर्फ सुनील कुमार उर्फ बुद्धवा के सहयोग से इस घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले से भाई अनजान था। इस लिए पुराने विवाद के आधार पर उसके द्वारा छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले से पर्दा हटाते हुए बताया कि जब घटना की वैज्ञानिक जांच की जाने लगी तो सभी बातें सामने आने लगी। दरअसल, राजमुनी देवी का अवैध संबंध पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी मोनू उर्फ बुद्धवा से था। पति इस प्रेम प्रसंग में बाधक बनता था, जिसके कारण दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का मन बनाया। इसी सोची समझी साजिश के तहत पत्नी राजमुनी ने छोटन की सब्जी में नींद की गोली डाल दी थी। जिससे वह बेसुध हो गया था। उसके बाद दोनों ने मिलकर गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को बधार में फेंक दिया। घटना के कुछ ही दिन बाद राजमुनी देवी और मोनू एक दूसरे से खुलेआम मिलने जुलने लगे। जिससे परिजनों का शक भी गहरा होने लगा। अंततः पुलिस जांच में मामला साफ हो गया। फिलहाल दोषियों को उसके सही ठिकाने पर पुलिस पहुंचा चुकी है।

धनबाद के पूर्व एसपी शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की बहन का निधन, जालान अस्पताल में चल रहा था इलाज

सिंदरी । धनबाद के पूर्व एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा की बहन अनीता प्रसाद का मंगलवार को निधन हो गया। वह 60 वर्ष की थीं। तबीयत खराब होने के बाद सोमवार को धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को उनका निधन हो गया। उच्च रक्तचाप की शिकायत थी। चिकित्सकों ने मौत का कारण हृदयाघात बताया है। अनीता प्रसाद के पति डॉ. शशि भूषण प्रसाद झरिया सह जोड़ापोखर चिकित्सा केंद्र के वर्षों तक प्रभारी थे। 5 साल पहले उनका निधन हो गया था। अनिता प्रसाद को दो पुत्री सुजा प्रसाद और नेहा प्रसाद है, दोनों पुत्री विवाहित हैं। सुजा प्रसाद कनाडा में अपने पति के साथ रहती है और सुजा भी एमएनसी में काम करती हैं। नेहा प्रसाद बेंगलुरु में अपने पति अशोक कुमार के साथ है और पति पत्नी दोनों काम करते हैं। मां के निधन का समाचार मिलते ही नेहा अपने पति अशोक कुमार के साथ फ्लाइट से बेंगलुरु से कोलकाता आ चुकी है और सड़क मार्ग से सिंदरी आ रही हैं। नेहा के ससुर शंभू प्रसाद ने बताया कि अनीता प्रसाद का शव धनबाद से सिंदरी स्थित उनके आवास पर लाया गया। दाह संस्कार मोहलबनी श्मशान घाट पर करने का निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु से नेहा के सिंदरी आने के बाद ही दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरु होगी। अनीता प्रसाद धनबाद की पूर्व सांसद प्रो. रीता वर्मा की ननद थीं।

पंचायत सदस्यों के वोटों पर लगने लगी बोली, 5 से 50 लाख तक पहुंचा भाव

लखनऊ । पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से चुनाव जीते तीन जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के खेमे में नजर आ रहे हैं। सपाइयों का दावा है कि प्रत्येक सदस्य ने 40 लाख रुपये लेकर अपनी निष्ठा बदली है। उधर, दलबदल करने वालों को कहना है कि टिकट लेने और चुनाव जीतने में किए गए खर्च की भरपाई करनी है। इनकी तो चांदी हो गई है। मोटी रकम पाने की चाहत में दलीय निष्ठा बदलने लगे हैं।

वोटों की खरीद फरोख्त का यह सिलसिला अमूमन सभी जिलों में जारी है। पांच लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक कीमत पहुंच रही है। जहां मुकाबला कड़ा है, वहां वोटों की बोली आसमान छू रही है। नगदी के अलावा लक्जरी गाड़ी का मोलभाव भी होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में हो रहा विलंब उम्मीदवारों को भारी पड़ता जा रहा है।

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम पिछले महीने पांच-छह मई को घोषित हो चुके हैं, लेकिन अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुखों के चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव 20 जून तक संभावित हैं। इसके बाद ब्लाक प्रमुखों के चुनाव जुलाई माह के प्रथम पखवाड़े में कराए जा सकते हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव ग्रामीण राजनीति का रुख निर्धारित करने वाला माना जाता है। इसलिए सभी प्रमुख दल इसको गंभीरता से लेते है। सदस्यों के वोटों से होने वाले इन चुनावों में वर्चस्व बनाने के लिए सत्तापक्ष की ओर से पूरी ताकत लगायी जाती है, वहीं मुख्य मुकाबले में आने की होड़ विपक्षी दलों में भी होती है।

बाहरी से गुरेज नहीं, केवल जिताऊ जरूरी – अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए धनबल और बाहुबल जरूरी है। प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में से 65 से अधिक पर अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी ताकत लगाए हुए है। चुनाव जीतने का समीकरण बनाने के लिए बाहरी उम्मीदवारों पर दांव लगाने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। ऐसे में छोटे दलों की मुश्किलें बढ़ती हैं। उनके समर्थन से चुनाव जीते सदस्यों को दलबदल से रोक पाना आसान नहीं है। सपाइयों का दावा है कि 50 से अधिक जिला पंचायत अध्यक्ष उनके होंगे।

जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा अपना दल एस – अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि उनकी पार्टी कुछ सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के चुनाव भी लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की याद में वर्चुअल माध्यम से सोमवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अनुप्रिया ने कहा कि पंचायत चुनाव की पार्टी माइक्रो स्तर पर समीक्षा करेगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

कोरोना वैक्सीन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यू-टर्न, कहा- भारत सरकार का टीका हम भी लगवाएंगे

लखनऊ । समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के कोरोना वैक्सीन लगवाने के एक दिन बाद ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यू-टर्न ले लिया है। मंगलवार को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उनके सुर बदले हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के टीके के खिलाफ थे, लेकिन भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। इससे पहले अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन को भाजपा का टीका बताते हुए इसे न लगवाने की बात कही थी।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंदलवार को ट्वीट कर लिखा कि जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे व टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं।

अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को लगवाई वैक्सीन – समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में कोरोनारोधी टीके की पहली डोज ली है। बताया जाता है कि इस दौरान मुलायम सिंह के साथ सपा अध्यक्ष व उनके पुत्र अखिलेश यादव और परिवार के कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे। अखिलेश यादव शुरू में जीवनरक्षक वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन बता चुके हैं। मुलायम सिंह यादव कुछ समय पहले कोरोना पाजिटिव हो गए थे। वह समय-समय पर अपने सेहत की जांच कराने को लेकर मेदांता अस्पताल आते रहते हैं। सोमवार को उनका आना इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

मुलायम से प्रेरणा लें सपाई, अखिलेश मांगें माफी – समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के वैक्सीन लगवाने की भाजपाइयों ने सराहना की तो साथ ही सपाइयों को नसीहत भी दी। वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव द्वारा टिप्पणी करने की याद दिलाते हुए अफवाह फैलाने पर माफी मांगने की मांग की। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने वैक्सीन लगवाते हुए मुलायम सिंह यादव की फोटो ट्विटर पर टैग की और सपाइयों पर तंज किया।

लापता चिराग पासवान को ढूंढ़ने वाले को मिलेगा इनाम, सांसद की तलाश के लिए बिहार में लगा पोस्टर

जमुई । बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने वाले सांसद चिराग पासवान को जमुई की जनता तलाश रही है। इसके लिए जनशक्ति विकास पार्टी ने कचहरी चौक पर लापता होने का पोस्टर लगाया है। सांसद की जानकारी देने वाले के लिए ईनाम भी रखा गया है लेकिन ईनाम की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। पोस्टर में जमुई की माटी का हूं यहीं से लड़ूंगा चुनाव का पुराना बयान चस्पा कर सवाल पूछा गया है कि चुनाव ही लड़ेंगे या इस कोरोना जैसी आपदा में जमुई की माटी का कर्ज भी उतारेंगे। चिराग के लापता होने का पोस्टर लगाए जाने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विरोधी चटकारे लेकर इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने में कोई भी कसर बांकी नहीं छोड़ रहे। वहीं युवा वर्ग भी पोस्टर के साथ और भी कई तीखे सवाल दाग सांसद समर्थक को निरुत्तर कर दिया है।

गत विधानसभा चुनाव के बाद लंबे समय से चिराग पासवान के अपने निर्वाचन क्षेत्र से गायब रहने को लेकर मंगलवार को जनशक्ति विकास पार्टी (डे.) द्वारा शहर के कचहरी चौक पर लापता होने के दर्जनों पोस्टर और बैनर लगा दिए गए। पोस्टर लगाए जाने के बाद अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि लोगों ने माना है कि सांसद लंबे समय से जमुई में दर्शन नहीं दिए हैं इसलिए आम जनता में उनके प्रति असंतोष देखा जा रहा है।

खास करके कोरोना काल में उनकी अनुपस्थिति को लेकर जमुई के आम लोगों के बीच खासी नाराजगी है। पोस्टर लगाने वाले जनशक्ति विकास पार्टी (डे.) के जमुई निवासी संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि माननीय सांसद चिराग पासवान जमुई लोकसभा के 18 लाख वोटरों के प्रतिनिधित्वकर्ता है। क्षेत्र की जनता के प्रति उनकी अपनी जबाबदेही है।

खासकर कोरोना जैसी आपदा में उनका गायब रहना दुखद है। चुनाव के वक्त जमुई को अपनी मां और माटी बताकर वोट लेने वाले सांसद अगर विपदा काल में लापता हैं तो यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और जमुई की जनता के लिए छलावा है। अगर यही रवैया रहा तो आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी विदाई सौ फीसदी तय है। वैसे भी सात वर्षों के कार्यकाल में उनके द्वारा विकास के नाम पर सिर्फ हवाबाजी और चिट्ठी बाजी की गई है। आधारभूत संरचना की बात तो छोड़िए सड़क पानी बिजली जैसी आम जरूरतों के लिए भी उनका प्रयास नगण्य है। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि बिहार विधानसभा में अपनी करारी हार के बाद वो डिप्रेशन में चले गए हों। इसलिए वो अपने क्षेत्र से गायब है। पोस्टर में इस बात का भी जिक्र है कि लापता सांसद के पता बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। अब यह देखना होगा कि इस पोस्टर बाजी के बाद सांसद कितना जगते है और जमुई की जनता को कब दर्शन देते है।

टाइफाइड से ग्रसित है सांसद- सांसद चिराग पासवान पिछले डेढ़ महीना से टाइफाइड से ग्रसित हैं। इस बात की जानकारी ट्वीट कर उन्होंने दी थी। लोजपा के जिलाध्यक्ष जीवन सिंह बताते हैं कि सांसद चिराग पासवान ने जितना कुछ जमुई के लिए किया इसके पहले किसी सांसद ने नहीं किया था।

इसके बावजूद चंद विरोधियों द्वारा उन्हें लापता बताए जाने का प्रयास राजनीति का घिनौना पन है। यह सभी जानते हैं कि वह अप्रैल माह में टाइफाइड से ग्रसित हो गए थे जिसका असर अब भी उनके ऊपर मौजूद है। नतीजतन वे फिलहाल क्षेत्र में समय दे पाने में असमर्थ हैं। स्वस्थ होते ही एक बार फिर पुराने अंदाज में क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। 8 मई को तबीयत खराब होने पर कोरोना जांच कराई परंतु निगेटिव निकला। बाद में बुखार रहने लगा। इसबार जांच में टाइफायड निकला। 13 मई को ट्वीट कर जानकारी साझा किया गया है। अभी भी कमजोरी है। इलाज कर रहे चिकित्सक ने आराम करने की सलाह दी है।

यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त, सिर्फ शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए मंगलवार का दिन मंगलकारी सिद्ध हुआ है। पिछले दो महीने से ज्यादा वक्त से कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में लगातार कम हो रहे संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर करने का ऐलान कर दिया है। राज्य के सभी जिलों में 600 से कम सक्रिय केस हो गए हैं। अब सिर्फ शाम सात बजे से सुबह सात बजे नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह व्यवस्था नौ जून बुधवार से लागू हो जाएगी।

यूपी सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में सफल सिद्ध हुई है। इसी का परिणाम है कि लगातार संक्रमण के केस कम हो रहे हैं। प्रदेश सरकार का दावा है कि 25 करोड़ की आबादी के बाद भी यूपी में जितने एक्टिव केस बचे हैं उतने कई राज्यों में नए केस आ रहे हैं। अब प्रदेश में कुल सक्रिय केस 14 हजार बचे हैं। पिछले 24 घंटे में 2.85 लाख लोगों की कोरोना जांच में 797 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब राज्य का पॉजिटिविटी रेट 0.2 फीसद और रिकवरी रेट 97.1 फीसद है।

उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी 75 जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया था। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू और शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी की। इन प्रयासों से जब संक्रमण के मामले लगातार घटने लगे तो सरकार ने व्यवस्था बना दी कि जिन-जिन जिलों में 600 से कम सक्रिय मामले होंगे, उन्हें सप्ताह में पांच दिन कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। इस तरह बड़ी तेजी से जिलों में सुधार होता गया और अब सभी 75 जिले कोरोना कर्फ्यू छूट पा चुके हैं। नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी अभी लागू रहेगी।

योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना प्रबंधन की समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि प्रदेश के सभी जिलों में अब 600 से कम कोरोना के सक्रिय केस हो गए हैं। इस पर निर्देश दिया कि अब सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत दे दी जाए। अब बुधवार से निर्धारित नियम-शर्तों के साथ बाजार खोलने व अन्य गतिविधियों की अनुमति दे दी जाएगी। हालांकि, सीएम योगी ने कोविड-19 से बचाव और इलाज की व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा सभी के सम्मिलित सहयोग और प्रयास से कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम में सफलता मिली है। संक्रमण की चेन हर स्तर पर तोड़ने के लिए प्रभावी प्रयास जारी रहने चाहिए।

देवभूमि उत्तराखंड में साल-दर-साल बढ़ रही बेटियां, लिंगानुपात 922 से बढ़कर हुआ 949

देहरादून । करीब 80 फीसद साक्षरता दर वाले उत्तराखंड में बेटियां साल-दर-साल बढ़ रही हैं। राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में लगातार सुधार हो रहा है। सरकारी आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2017-18 में जन्म के समय लिंगानुपात 922 था। यानी, प्रति हजार बालकों पर इतनी बालिकाओं का जन्म हो रहा था। वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा बढ़कर 938 और वर्ष 2019-20 में 949 पहुंच गया।

नीति आयोग के निष्कर्षों के आधार पर मीडिया के एक वर्ग में उत्तराखंड में जन्म के समय लिंगानुपात को लेकर आई खबरों के बाद महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य ने सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जन्म के समय लिंगानुपात में लगातार सुधार हो रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य के पांच जिले बागेश्वर, अल्मोड़ा, चम्पावत, देहरादून व उत्तरकाशी देश के 50 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में शामिल हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पिछले वर्ष 24 सितंबर को राज्य को भेजे गए पत्र से इसकी पुष्टि होती है। यही नहीं, योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार तीन बार राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कर चुकी है। वर्ष 2019 में देहरादून जिले को देश के 16 सर्वश्रेष्ठ जिलों में शामिल कर योजना में समुदाय की प्रभावी सहभागिता, सितंबर 2019 में ऊधमसिंहनगर जिले को जन्म के समय बेटियों के लिंगानुपात में वृद्धि और मार्च 2020 में प्रचार-प्रसार की नवाचार पहल के लिए देश के 25 जिलों में शामिल होने पर पुरस्कृत किया गया। राज्यमंत्री आर्य ने कहा कि प्रदेश में इस योजना को अब और अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा।

दरभंगा में कागजी कार्रवाई के बूते मानसून से निपटने को तैयार नगर निगम प्रशासन

दरभंगा । जून का महीना शुरू हो गया है। परीक्षा का कांउडाउन चालू हो गया है। यह परीक्षा किसी विद्यार्थी के लिए बल्कि नगर निगम की होती है। सो, निगम प्रशासन की धड़कनें तेजी से धड़कने लगती है।मानसून इस महीने के दूसरे हफ्ते में दस्तक देने को है। सो, अभी से ही हाथ-पांव फूल रहे है। शहरवासियों के भी और नगर निगम प्रशासन के भी। डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत शहरवासियों पर पूरी तरह से फिट नजर आती है। किसी तरह निगम प्रशासन डूबते-डूबते लोगों की नैया पार कराती है। प्रतिवर्ष बारिश में शहर की सूरत बिगड़ जाती है। आधे से अधिक वार्डों में जलजमाव की समस्या बनी रहती है। कई इलाकों में एक से दो फीट तक पानी लगा रहता है। सो, नगर निगम प्रशासन की किरकिरी भी लाजमी है। सो, होती रहती है। निगम पदाधिकारी और कर्मी भी इसे अपनी नियति मान चुके है। इसलिए हर साल बारिश के समय शहर को जलमुक्त कराने का दंभ भरते रहते है। लेकिन, हर वर्ष अग्नि परीक्षा में फेल साबित होते है। जलजमाव से निपटने के लिए कार्य योजना पर बहुत चर्चा होती है। पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। खानापूरी के नाम पर नालों की आंशिक रूप से सफाई भी होती है। लेकिन, इससे समस्याएं खत्म नहीं होती है। शहरी क्षेत्र के कई नालों पर आज भी अतिक्रमणकारी काबिज है। इन्हें अब तक खाली नहीं कराया गया है। घोषणाएं बड़ी-बड़ी होती है। लेकिन, काम धरातल पर नजर नहीं आता है। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र को जलजमाव से मुक्त कराने को लेकर लगातार दो बैठकें की।

चंडीगढ़ पीयू प्रशासन ने हॉस्टल रुम अलॉटमेंट को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश

चंडीगढ़ । पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर नए रुल्स की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस फैसले से अब कई पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को दिक्कतें आ सकती हैं। नए नियमों के तहत अगर किसी रिसर्च स्कॉलर का गाइड पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर है तो उसे पीयू कैलेंडर के तहत हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होगी। बीते कई दिनों से पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर लगातार छात्र संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। पीयू डीएसडब्ल्यू की ओर से जारी पत्र में साफ किया गया है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को हॉस्टल रुम अलॉट होगा जिनके गाइड पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के विभागों में पढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजों के भी प्रोफेसर को अब रिसर्च गाइड बनने की अनुमति मिल चुकी है। पीयू के काफी स्टूडेंट्स कॉलेज प्रोफेसर के अंडर पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए लाइब्रेरी और अन्य जानकारी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में आना पड़ता है। पीयू के रीजनल सेंटर के प्रोफेसर की देखरेख में भी कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन पीयू प्रशासन ने ऐसे सभी रिसर्च स्कॉलर को अब हॉस्टल अलॉटमेंट से इंकार कर दिया है।

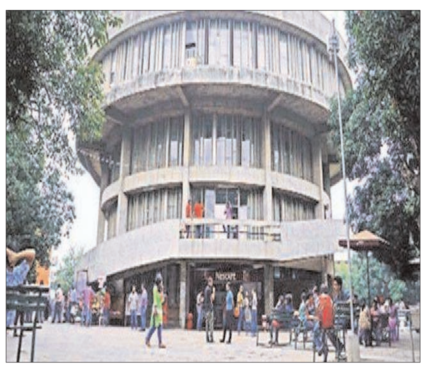

रिसर्च स्कॉलर की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित- पंजाब यूनिवर्सिटी में हर साल 350 से 400 के करीब रिसर्च स्कॉलर पीएचडी डिग्री हासिल करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण बीते डेढ़ साल से रिसर्च स्कॉलर की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कैंपस और लाइब्रेरी बंद होने के कारण रिसर्च स्कॉलर अपना शोधवर्क अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। पीयू प्रशासन ने अधिकतर रिसर्च स्कॉलर को भी कमरा खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शोधकर्ताओं को मजबूरी में घरों को जाना पड़ा है। छात्र नेताओं का कहना है कि शोध वर्क के लिए कई बार टाइमलाइन तय होती है। लेकिन कोरोना महामारी में स्टूडेंट्स फिल्ड वर्क नहीं कर पाए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 20 हॉस्टल में 6 हजार से अधिक लड़के और लड़कियों को हर साल हॉस्टल अलॉटमेंट की जाती है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन दिनों सभी हॉस्टल में सिर्फ 400 के करीब स्टूडेंट्स ही रह रहे हैं। पीयू कैंपस गर्ल्स और ब्वॉयज हॉस्टल में सिर्फ एक-एक मैस स्टूडेंट्स के लिए खोली गई है।

धरने पर बैठे छात्र नेता- बीते कई दिनों से एसएफएस छात्र संगठन के छात्र नेता और समर्थक पीयू कैंपस और लाइब्रेरी खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन करन रहे हैं। पीयू के प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर स्टूडेंट्स ने डेरा डाला हुआ है। स्टूडेंट्स के विरोध को देखते हुए पीयू प्रशासन को कई बार पुलिस बल तक बुलाना पड़ा है। उधर, पीयू अधिकारियों के अनुसार नौ जुन के बाद ही हॉस्टल अलॉटमेंट और लाइब्रेरी खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा। पीयू प्रशासन केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन के निर्देशों पर ही कैंपस खोलने पर फैसला लेता है।

10वीं व 12वीं में प्रमोट करने के फार्मूले पर यूपी बोर्ड ने पेरेंट्स व स्टूडेंट्स मांगी राय

लखनऊ । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा रद होने के बाद अब 56 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नति देने के लिए फार्मूला तैयार किया जा रहा है। सोमवार को इस सिलसिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों व अभिभावकों के साथ एक आनलाइन बैठक आयोजित की। बैठक में वार्षिक परीक्षा व प्री बोर्ड के अंकों के औसत अंकों के आधार पर ही छात्रों को प्रोन्नति देने की सलाह अभिभावकों व शिक्षकों ने दी। प्रोन्नति के संबंध में कोई भी शिक्षाविद, अभिभावक, छात्र व आमजन ईमेल आइडी upboarde&amination@gmail.com पर मेल कर अपने सुझाव दे सकता है।

अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों व अभिभावक संघों के प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में सलाह दी गई कि इंटरमीडिएट का परीक्षाफल कक्षा 10 में प्राप्त प्रतिशत, कक्षा 11 के अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा और कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा के औसत अंकों के आधार पर तैयार किया जाए। सर्वोदय इंटर कालेज फतेहपुर के प्रधानाचार्य जवाहर सिंह राठौर ने सुझाव दिया कि हाईस्कूल का रिजल्ट कक्षा नौ की वार्षिक परीक्षा तथा कक्षा 10 की प्री बोर्ड या अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को प्रोन्नति दी जाए। फतेहपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष आत्माराम ने सुझाव दिया कि हाईस्कूल का रिजल्ट कक्षा 10 के प्री-बोर्ड व कक्षा नौ की वार्षिक परीक्षा के औसत अंकों के आधार पर ही तैयार किया जाए। महेंद्र टेक्निकल इंटर कालेज चंदौली के प्रधानाचार्य डा.रामचंद्र शुक्ला ने सुझाव दिया कि कक्षा 10 व कक्षा 12 की प्री-बोर्ड परीक्षा के अंकों को ज्यादा महत्व दिया जाए।

हैदराबाद में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।

कुल्लू के एक क्षेत्रीय अस्पताल में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक महिला को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देती हुई।

कन्याकुमारी जिले के हिंदू कॉलेज में नागरकोइल नगर निगम द्वारा आयोजित एक टीकाकरण शिविर में एक महिला कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्राप्त करते हुए ।

एक नजर

डेल्टा वैरिएंट से महामारी की तीसरी लहर का खतरा, 40 फीसद अधिक खतरनाक

नई दिल्ली । देश में महामारी की दूसरी लहर के जिम्मेवार डेल्टा वैरिएंट क्1.617.2 का असर अब कमजोर होने लगा है लेकिन दुनिया के अन्य देशों में अभी यह परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वैरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा नाम दिया है। इस वैरिएंट से संक्रमण का पहला मामला पिछले साल अक्टूबर में भारत में ही आया था। कोरोना वायरस के इस डबल म्यूटेंट वैरिएंट डेल्टा ने देश में तबाही मचा दी, और लाखों लोगों को चपेट में ले लिया। बता दें कि डेल्टा वैरिएंट के बाद अब नए वैरिएंट के आने की खबरें हैं। WHO का कहना है कि वायरस के अन्य वैरिएंट अल्फा, बीटा, गामा की तुलना में डेल्टा अधिक खतरनाक है और यह कई गुना तेजी से फैलता है। संगठन ने यह भी कहा जिंदगियों के लिए सबसे अधिक घातक भी यही वैरिएंट है।ब्रिटेन में भी डेल्टा वैरिएंट का खौफ है। यहां महामारी की तीसरी लहर का जिम्मेवार भी इसी वैरिएंट को बताया गया है। यहां के स्वास्थ्य मंत्री मैन हेनकॉक के अनुसार बाकी दोनों वैरिएंट की तुलना में डेल्टा 40 फीसद अधिक खतरनाक है। वहीं सीनियर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हालिया बढ़ोतरी के पीछे डेल्टा है। इसने 21 जून से निर्धारित अनलॉक योजना को और मुश्किल बना दिया है। उन्होंने बताया कि डेल्टा से संक्रमित अस्पताल में भर्ती अधिकतर लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं मिली थी। ब्रिटेन में जिन लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है उनपर भी इसका खतरा है जो चिंता का विषय है। ब्रिटेन में डेल्टा वैरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां इस वैरिएंट के अब तक कुल 12 हजार से यादा केस मिले हैं।

रेलवे कर्मियों ने शुरू किया अभियान, कहा- मिले फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा

नई दिल्ली । कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए रेलकर्मी कोरोना योद्धा का दर्जा पाने के लिए आंदोलित हो उठे हैं। आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) के आह्वान पर सोमवार को देशभर के रेल कर्मचारियों ने ट्विटर पर अपनी मांग को लेकर अभियान चलाया। रेल कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेलवे अधिकारियों को ट्वीट करके कोरोना के खिलाफ लडाई में योद्धा का दर्जा देने की मांग की है। एआइआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद रेल कर्मचारी ट्रेनों की आवाजाही और जरूरी सामान की ढुलाई सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। आक्सीजन की कमी दूर करने के लिए आक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर कई लोगों की जान बचाई गई। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काफी संख्या में रेल कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए है, कई लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि जान की परवाह किए बगैर रेल कर्मचारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद इनकी जायज मांगें नहीं मानी जा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दूसरे विभागों के कर्मचारियों की तरह रेल कर्मचारियों को योद्धा का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से इन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता नहीं मिल रही है। यदि किसी रेल कर्मचारी की संक्रमण से मौत हो रही है तो उसके स्वजन को 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद से वंचित किया जा रहा है।

कश्मीर के इस गांव के नाम कोरोना से जंग का रिकॉर्ड, बना 100 फीसदी टीकाकरण वाला पहला गांव

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के वावेन गांव ने 100 फीसदी कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस गांव के 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस तरह से यह देश का पहला गांव है, जहां 100 फीसदी टीकाकरण हो चुका है। इस गांव में टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जहां ग्रामीणों ने जागरुकता दिखाई है तो वहीं स्वास्थ्यकर्मियों ने भी कड़ी मशक्कत की है। जंगलों के बीच बसे इस गांव तक पहुंचने के लिए हेल्थ वर्कर्स को 11 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता था। बीते शुक्रवार को जब हेल्थ वर्कर्स की टीम इस गांव में पहुंची तो सभी 362 ग्रामीणों ने टीका लगवा लिया। गांव में यादातर आबादी जनजातीय समुदाय की है, जो हमेशा गर्मियों में पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं और अपने पशुओं संग पतझड़ के सीजन में ही लौटते हैं। बांदीपोरा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. मसरात ने कहा कि गांव में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लग चुका है। उन्होंने कहा कि यदि हम इंतजार करते तो ये लोग पहाड़ों की ओर निकल जाते और फिर उन्हें टीका लगा पाना मुश्किल होता। ऐसे में हमने पहले ही यह टारगेट हासिल कर लिया है। अब अगला टीका 12 सप्ताह के गैप पर लगेगा और हमने उनसे उनके रूट के बारे में पूछ लिया है ताकि उन्हें पहाड़ों पर ही कहीं जाकर टीके लगाए जा सकें। डॉक्टर मसरात ने कहा कि यदि हम उन्हें अभी टीका नहीं लगा पाते तो फिर अक्टूबर में उनके लौटने तक इंतजार करना पड़ता।

पंजाब से राजस्थान में फिर आया कैमिकल युक्त पानी, हर बार नहर में छोड़ा जाता है सीवरेज का पानी

जयपुर। राजस्थान के 8 जिलों में पानी की आपूर्ति करने वाली इंदिरा गांधी नहर में गंदा और कैमिकल युक्त पानी आने से संकट हो गया है। पंजाब के हरिक बैराज से छोड़ा गया गंदा और केमिकल युक्त पानी सोमवाार को हनुमानगढ़ जिले में पहुंचा और मंगलवार को बीकानेर तक पहुंच गया। अब आगे अन्य जिलों में जाएगा। राज्य के 8 जिलों के करीब 2 करोड़ लोग यही पानी पीते हैं। सिंचाई भी होती है। हर बार होने वाली नहर बंदी के बाद पंजाब की तरफ से ऐसा पानी छोड़ा जाता है। पिछले दिनों ही नहर बंदी खत्म हुई है। इंदिरा गांधी नहर में 60 दिन की नहर बंदी के बाद मई के अंत में हरिके बैराज से पानी छोड़ा गया था। इस समय केवल पीने का पानी ही छोड़ा जा रहा है। इस कारण यह कैमिकल युक्त पानी सभी जगह पहुंचेगा। पंजाब की फैक्ट्रियों का पानी हर बार नहर में डाले जाने को लेकर आंदोलन भी होते हैं, लेकिन कोई स्थाई समाधान नहीं निकल सका है। राजस्थान के किसानों ने इस संबंध में एक बार पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर कर स्थाई समाधान की मांग की थी। ट्रिब्यूलन ने पंजाब सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना भी किया था। वहां की सभी फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश भी हुए थे, लेकिन दूषित पानी आना अभी बंद नहीं हुआ। राज्य जलसंसाधन विभाग के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल का कहना है कि पंजाब के मुख्य अभियंता सहित अन्य अधिकारियों को पंजाब की फैक्ट्रियों के कैमिकल युक्त पानी आने की सूचना दी गई है। यह पानी लुधियाना की फैट्रियों का अपशिष्ट है। उम्मीद है शीघ्र ही हरिक बैराज से साफ पानी की आवक शुरू हो जाएगी। श्रीगंगानगर के सांसद निहालचंद मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से इस संबंध में बात कर हर बार होने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा । उन्होंने कहा कि वे किसानों के साथ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मिलेंगे ।

केंद्र की ओर से आखिरी नोटिस पर ट्विटर ने दिया जवाब, कहा- हम भारत के प्रति प्रतिबद्ध, सरकार से बातचीत जारी

नई दिल्ली । विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में तय नए नियमों को लेकर ट्विटर की आनाकानी पर केंद्र सरकार नकेल कस रही है। नए नियमों के अनुपालन को लेकर पिछले शनिवार को माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्विटर को केंद्र सरकार की ओर से आखिरी नोटिस भेजा गया। इस नोटिस का ट्विटर ने जवाब दाखिल किया है। ट्विटर ने कहा कि ट्विटर भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा। हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और हमारी प्रगति का अवलोकन विधिवत साझा किया गया है। हम भारत सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे।

यह कदम उठा सकती है सरकार- केंद्र सरकार के नोटिस में कहा गया था कि यह आखिरी चेतावनी है। अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आइटी कानून और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म किया जा सकता है, जिससे ट्विटर को मिली हुई कई छूट समाप्त हो जाएगी। इससे ट्विटर के लिए भारत में संचालन मुश्किल हो सकता है।

प्रतिबद्धता में कमी- इंटरनेट मीडिया से जुड़े नियमों के पालन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि नियमों के पालन में कोताही से भारत के लोगों के प्रति ट्विटर की प्रतिबद्धता में कमी जाहिर होती है। 26 मई से नए नियम लागू हो चुके हैं। इसके तहत सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को शिकायतों के निवारण के लिए चीफ कंप्लायंस आफिसर के साथ नोडल आफिसर और रेसीडेंट ग्रीवांस आफिसर नियुक्त करना है।

ट्विटर का टाल-मटोल वाला रवैया- मंत्रालय ने नोटिस में कहा था कि ट्विटर ने अब तक चीफ कंप्लायंस आफिसर की नियुक्ति को लेकर कोई सूचना नहीं दी है। वहीं, नोडल आफिसर और ग्रीवांस आफिसर भी भारत में ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं, जो कि नए नियमों के खिलाफ है। ट्विटर ने भारत में अपने कार्यालय का जो पता दिखाया है, वह किसी लॉ फर्म का है। यह भी आइटी नियमों के खिलाफ है।

नियमों के पालन में दिलचस्पी नहीं- नोटिस में कहा गया था कि पिछले एक दशक से ट्विटर भारत में कारोबार कर रहा है। इसके बावजूद इंटरनेट मीडिया के नियमों के पालन को लेकर ट्विटर कोई मैकेनिज्म तैयार करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, जिससे भारत में ट्विटर यूजर्स अपनी शिकायतों का निपटारा एक पारदर्शी प्लेटफार्म पर कर सकें।

पारदर्शी व्यवस्था बनाए- सरकार का कहना है कि ट्विटर पर जिन लोगों को गाली दी जाती है, जो ट्विटर की वजह से यौन हिंसा के शिकार होते हैं, उन्हें अपने मामलों के निपटारे के लिए ट्विटर के पारदर्शी मैकेनिज्म की जरूरत है। ट्विटर सरकार के निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान लाल किले पर हुए उपद्रव से जुड़े ट्वीट को भी सरकार ने हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें ट्विटर ने बहुत आनाकानी की थी।

पिछले दिनों नए नियमों के अनुपालन पर तकरार बीच, ट्विटर ने ब्लू टिक पर भी खेल शुरू कर दिया है। शनिवार को ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व संघ के कई पदाधिकारियों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। बाद में चारों ओर से दबाव के बाद इनके ब्लू टिक रीस्टोर कर दिए गए।

लिव-इन में रह रही 17 साल की नाबालिग और 20 साल के लड़के को हाइकोर्ट ने दी सुरक्षा

नई दिल्ली । पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव-इन में रह रहे एक ऐसे जोड़े को सुरक्षा प्रदान की है जिसमें लड़के की उम्र 20 साल और लड़की की उम्र 17 साल है। 17 साल की नाबालिग लड़की को लिव-इन में रहने के लिए सुरक्षा देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि ये दोनों साथ रहना चाहते हैं तो इसमें अदालत कुछ नहीं कर सकती है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि जोड़े ने हमसे शादी या अपने रिश्ते को मंजूरी देने की अनुमति नहीं मांगी है अगर ऐसा होता तो कोर्ट को मुश्किल होती चूंकि लड़की नाबालिग है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का यह आदेश पंजाब के बंठिडा में रहने वाली 17 साल की लड़की और 20 साल की लड़के की सुरक्षा याचिका पर आया है। जस्टिस संत प्रकाश की बेंच ने 3 जून को जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया था। यहां ध्यान दिए जाने वाली बात यह है कि लड़की नाबालिग है और शादी करने के योग्य नहीं है। इस फैसले से पता चलता है कि हाई कोर्ट की विभिन्न बेंचों में लिव-इन को लेकर अलग-अलग तरह के विचार हैं।

अदालत को बताया गया कि लड़की और उसके साथी के रिश्ते के बारे में पता चलने पर लड़की के माता-पिता चाहते थे कि वह उनके पसंद के लड़के से शादी करे, जिसके बाद लड़की अपने साथी के साथ रहने के लिए घर छोड़ आई। उन्होंने तब तक साथ रहने का फैसला किया है जब तक उन्हें कानूनी रूप से अपनी शादी की अनुमति नहीं दी जाती है। पीठ ने कहा, अगर शादी की पवित्रता के बिना एक साथ रहने का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा से वंचित किया जाता है, तो ऐसा करना न्याय का मजाक होगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यहां हो रही हॉनर किलिंग की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इनकी सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने उनसे शादी करने या अपने रिश्ते को मंजूरी देने की अनुमति नहीं मांगी है। अगर ऐसा होता तो अदालत के लिए मुश्किल हो जाती।

लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य- इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की ने सुरक्षा की मांग करने वाले एक प्रेमी जोड़े की याचिका खारिज कर दी थी और याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप (सहजीवन) नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ता 19 वर्षीय गुलजा कुमारी और 22 वर्षीय गुरविंदर सिंह ने याचिका में कहा है कि वे एक साथ रह रहे हैं और जल्द शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कुमारी के माता-पिता से अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी।

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एचएस मदान ने अपने 11 मई के आदेश में कहा कि वास्तव में याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की आड़ में अपने लिव इन रिलेशनशिप पर अनुमोदन की मुहर की मांग कर रहे हैं, जो नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और याचिका में कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। लिहाजा याचिका खारिज की जाती है।

पीएमएवाई में हस्तेक्षप को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिखा पीएम मोदी को पत्र

हैदराबाद । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री आवास योजना में हस्तक्षेप को लेकर पत्र लिखा है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पीएमएवाई के तहत राज्य सरकारों को दी गई सहायता के हिस्से के रूप में ग्रीनफील्ड कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के निर्माण को शामिल करने और इस संबंध में मंत्रालयों को निर्देश देने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि PMAY, MoHua और ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए संचालित की जा रही है। जब भारत आजादी के 75 साल पूरे करेगा तो 2022 तक इडब्लयूएस वर्ग के लोगों को पक्का घर देने का वादा इस योजना के तहत किया गया है। सीएम ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 'सभी के लिए घर' के विजन को आगे बढ़ाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 68381 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करके हाउस साइट्स को वितरित किया है। 17005 ग्रीनफील्ड कॉलोनी में 30.76 लाख लाभार्थी हैं। इसकी अनुमानित लागत 23535 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 17005 ग्रीनफील्ड कॉलोनियोयों में 28.30 लाख पक्के घर पीएमएवाई अर्बन और ग्रामीण कार्यक्रम के तहत बना रहे हैं, जिसकी अनुमानित लागत 50,944 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करते हुए लिखा कि ग्रीनफील्ड कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराए बिना इस योजना का विजन पूरा नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राय सरकार इस कार्य में लगी हुई है, लेकिन अतिरिक्त लागत का भार राज्य सरकार पर पड़ रहा है।

अनलॉक होते राज्यों में कई सेवाएं हुई बहाल, मेट्रो और बसों के संचालन से कई जगह टूट रहे नियम

नई दिल्ली । देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही सड़कों पर लोगों के अलावा वाहनों की भी भीड़ बढ़ गई। अनलॉक के साथ ही केंद्र ने भी बंद पड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ा दिया गया है। इसमें बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात की ट्रेनें शामिल हैं। पश्चिम रेलवे ने भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है। दिल्ली की ही बात करें तो सड़कों पर भीड़ बढ़ने के साथ ही पुलिस और सिविल डिफेंस कर्मियों को सड़क पर उतरना पड़ा। दिल्ली में मेट्रो सेवा को भी 50 फीसद यात्रियों के साथ शुरू कर दिया गया है। हालांकि पहले ही दिन काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान कई बार नियमों को भी टूटता हुआ देखा गया।

मुंबई में भी राज्य परिवहन की बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के लिए अपनी राज्य परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू कर दिया है। राज्य के सभी जिलों में 600 से कम सक्रिय मामलों के बाद सभी जिलों में पाबंदियों में ढील दे दी गई है। हालांकि हर जिले में शाम सात बजे से सुबह सात बजे नाईट कर्फ्यू रहेगा

9 जून से नियम-शर्तों के साथ बाजार खोलने व अन्य गतिविधियों की अनुमति दे दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में 24 मई 2021 को प्रदेश के प्रमुख सचिव ने दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत प्रदेश में हवाई मार्ग से आने वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा।

इसके अलावा उन्हें सेल्फ डिक्लेयरेशन और टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि कोई भी यात्री में कोरोना संबंधी लक्षण पाए गए तो ऐसे यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। इसमें नेगेटिव आने पर ही वो घर जा सकेगा। पॉजीटिव पाए जाने पर यात्री को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा जहां उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा। ये आइसोलेशन 10 दिनों का होगा। सात दिन बाद यदि वो ठीक पाया जाता है तो उसको घर जाने की इजाजत होगी, लेकिन वहां पर सात दिन उसको आइसोलेशन में ही रहना होगा। यात्रियों की सघन निगरानी के लिये मोबाइल में आरोग्य सेतु एप का होना अनिवार्य है।

अनलॉक होते राज्यों को देखते हुए अब केंद्र सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि विमान सेवा का फायदा उठाने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य करने से छूट दे दी जाए।

ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए लाना बन रहा बड़ी चुनोती, कर्मचारियों के साथ युवा भी कर रहे जागरूकता लाने का प्रयास

जोधपुर । जहां कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए 45+ श्रेणी के तहत लाना चिकित्सा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। इसके तहत कोरोना के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण के साथ साथ टीकाकरण की धीमी रफ्तार के मध्य नजर गांव वासियों को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर टीकाकरण की धीमी रफ्तार एक चुनोती बन रही है।

इस चुनौती को देखते हुए कुछ गांवों के चिकित्सा कर्मचारी और कुछ जागरूक युवा इन ग्रामीणों को घर-घर जाकर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आगे आए हैं, जो कि स्थानीय भाषा मे लोगो से जनसंपर्क कर टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने में अपना योगदान दे रहे हैं।जोधपुर संभाग से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रो और पाली जालोर सिरोही के ट्राइबल इलाको में वेक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस कार्यक्रम में इन युवाओं की महत्ती भूमिका है। जोधपुर से ऐसे युवाओं में जोधपुर के दीक्षित परिहार ने ग्रामीणों में टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया है उन्हें टीकाकरण की महत्वता बता रहे है। ओसियां उपमंडल के गांवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस विकट स्थिति में टीकाकरण के लाभों के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए घर- घर जाकर ग्रामीणों से मिल रहे हैं । दीक्षित परिहार ने डोर टू डोर पैंपलेट बाटकर लोगो को जागरूक करने का भी काम किया। कोरोना टीके को लेकर ग्रामीणों में भय व अज्ञानता का माहौल है। ग्रामीणों को लगता है कि कोरोना का टीका लगवाने से मौत या कोई अन्य जटिलता हो सकती है। इस भय को दूर करने के लिए पाली जिले के पंचायत समिति से जुड़े गांव डरी से जुड़े पीईईओ रविन्द्र सिंह के निर्देशन में भी एक कोर कमेटी का गठन किया गया है। जो कि घर घर जनसंपर्क कर टीकाकरण के लाभ को आम जन तक पहुचा रहे हैं।

जिनमें पंचायत सहायकों की भी मदद कारगर साबित हुई है। पहले विद्यालय से जुड़े स्टाफ के ग्रामीणों के आवास पर जाने पर उनके साथ दुर्वव्यहार होता था।

दिसंबर तक 18 साल से यादा उम्र वाली पूरी आबादी को कैसे लगेगा कोरोना टीका, सरकार ने बताया पूरा प्लान

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने टीकाकरण नीति में बदलाव के साथ ही दिसंबर तक 18 साल से अधिक आबादी के सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना तैयार कर ली है। सरकार ने कहा कि जुलाई तक टीके की 53.6 करोड़ खुराक उपलब्ध हैं, जबकि अगस्त से दिसंबर के बीच 133.6 करोड़ खुराक का इंतजाम किया जा रहा है। इससे सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगा पाना संभव हो सकेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार टीकाकरण शुरू होने से लेकर जुलाई तक टीकों की उपलब्धता 53.6 करोड़ है। इसमें रायों एवं निजी अस्पतालों द्वारा सीधे तौर पर खरीदी गई 18 करोड़ डोज भी शामिल है। अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड की 50 करोड़, कोवैक्सीन की 38.6 करोड़, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़,, जायडस कैडिला की 5 करोड़ तथा स्पूतनिक के 10 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इन पांच महीनों में 133.6 करोड़ खुराक होगी। इस प्रकार जनवरी से दिसंबर तक कुल 187.2 करोड़ खुराक होंगी। जो 94 करोड़ वयस्क व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होंगी। भूषण के अनुसार यदि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन आदि से इस बीच टीके मिल जाते हैं, साथ ही घरेलू कंपनी जिनोवा का टीका तैयार हो जाता है या भारत बायोटैक की नेजल वैक्सीन तैयार हो जाती है, तो इससे टीकों की अतिरिक्त उपलब्धता होगी।

'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3' ने तोड़ा रिकॉर्ड, आईएमडीबी पर बनी सबसे ज्यादा रेटिंग वाली वेब सीरीज

पहले दो सीजन की सफलता के बाद, ऑल्ट बालाजी का 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' का तीसरा सीजन भी दिल जीत रहा है। मुख्य जोड़ी के रूप में सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी की विशेषता वाला यह रोमांस ड्रामा आईएमडीबी पर रिलीज होने के केवल एक सप्ताह के भीतर 9.3 रेटिंग के साथ सबसे अधिक रेटिंग वाले वेब शो में से एक बन गया है। डिजिटल दुनिया में पहले से ही धूम मचाने वाले इस शो को 29 मई को लॉन्च किया गया था जिसमें एंटरटेनमेंट के सभी गुण है और शानदार समीक्षा का पात्र बना हुआ है। अगस्त्य के रूप में सिद्धार्थ के आकर्षक व्यक्तित्व और मदहोश करने वाली मुस्कान ने निस्संदेह उन्हें आलोचकों, दर्शकों, इंडस्ट्री के दोस्तों और फर्टेर्निटी से बड़ी प्रशंसा दिलाई है, जिससे वह ओटीटी स्पेस में भी सबसे होनहार और सफल दावेदारों में से एक बन गए हैं। जब से मेकर्स ने सीजन 3 की घोषणा की थी, दर्शक बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। ये ही वजह है कि दर्शकों द्वारा इसके इंटेंस कैरेक्टर पोस्टर और दिलचस्प टीजर और ट्रेलर को खूब सरहाया गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह आईएमडीबी की सबसे प्रत्याशित नई भारतीय फिल्मों और शो में ट्रेंड कर रहा था। 8.8 से 9.3 रेटिंग तक, वेब शो ने लॉन्च के बाद से अपनी लोकप्रियता और दर्शकों के बीच दीवानगी में वृद्धि देखी है। रोजाना नए रिकॉर्ड बनाते हुए इस शो ने एक दिन में गूगल ट्रेंड्स में 100+ सर्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' फ्रेंचाइजी दर्शकों की पसंदीदा है क्योंकि यह उन्हें प्यार, लालसा और दिल टूटने के सफर पर ले जाती है।

परेशान होकर केआरके ने दी देश छोड़ने की धमकी, बोले- बॉलीवुड वालों को पछताना पड़ेगा

कमाल राशिद खान यानि केआरके का विवादों से पुराना नाता रहा है। केआरके इन दिनों सलमान खान से पंगा लेने की वजह से सुर्खियों में बने हुए है। सलमान के बाद केआरके ने सिंगर मीका सिंह से भी पंगा लिया। इसके बाद उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट लॉक कर लिया है। अब केआरके ने अपना अकाउंट वापस अनलॉक कर दिया है। इसके बाद उन्होंने देश छोड़ने की धमकी दी है। केआके का कहना है कि बॉलीवुड के कुछ लोग उन्हें तंग कर रहे हैं जिसके चलते वो एमएफ हुसैन की तरह हमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ज्यादा परेशान किया तो वह अपने विरोधियों की वीडियो लीक कर देंगे जो उनके पास है। केआके ने ट्वीट किया, मैं फिल्मों की समीक्षा करना बंद करने के बहुत करीब था लेकिन फिर मुझे लगा मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। और मुझे लगता है, मैं हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया हूं क्योंकि मेरे पास और संघर्ष करने की उम्र नहीं है। जिस तरह से बॉलीवुड के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं एमएफ हुसैन की तरह हमेशा के लिए भारत छोड़ सकता हूं। ताकि मुझे किसी केस का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा, बॉलीवुड के लोगों को यह समझना चाहिए कि वे मुझे कोर्ट में तभी बुला सकते हैं जब मैं भारत आना चाहता हूं। एक बार जब मैं स्थायी रूप से भारत छोड़ दूंगा तो कोई भी कानून मुझे फिल्मों की समीक्षा करने से नहीं रोक सकता। और अगर मैं भारत छोड़ दूंगा तो बॉलीवुड वालों को जीवन भर पछताना पड़ेगा क्योंकि भाईचारा खत्म हो चुका होगा। केआरके ने लिखा, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा। मेरे पास इतने सारे वीडियो और रहस्य हैं, कि मैं कई बॉलीवुड वालों के रहस्यों को उजागर करता हूं! और अगर मैं भारत छोड़ दूंगा, तो फिर मैं ये सब बड़ी धूम धाम से करूंगा। अच्छी तरह से नोट कर लेना, जो मैं आज कह रहा हूं (याद रखें कि मैं आज क्या कह रहा हूं)! मजे करो। वहीं केआरके ने अर्जुन कपूर को अपना खास दोस्त और उन्हें असली मर्द बताया है। उन्होंने ट्वीट किया, शुक्रिया अर्जुन भाई, आपकी कॉल और लंबी बातचीत के लिए। अब मैं समझा कि बॉलीवुड में सिर्फ आप ही मेरे अच्छे दोस्त हो और सिर्फ आप ही असली मर्द को जो किसी से नहीं डरता। अब मैं कभी आपकी फिल्मों का निगेटिव रिव्यू नहीं करूंगा। बता दें कि इससे पहले केआरके ने गोविंदा को सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहते हुए ट्वीट किया था। इस ट्वीट के बाद गोविंदा ने साफ किया था कि उनका केआरके से कोई कनेक्शन या दोस्ती नहीं है। इसके बाद केआरके ने भी कहा था कि उन्होंने किसी और गोविंदा की बात की थी।

2020 के मोस्ट डिजायरेबल मैन बने सुशांत सिंह राजपूत

द टाइम्स की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में अलग-अलग फील्ड के 40 साल से कम सबसे हैंडसम और चार्मिंग व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। 2020 की लिस्ट में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम टॉप पर है। ऑनलाइन वोट्स और इंटरनल जूरी के फैसलों के आधार पर जारी की गई इस लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत का नाम सबसे उपर है। सुशांत का पिछले साल 14 जून को निधन हो गया था। सुशांत एक होनहार कलाकार के साथ ही एक दार्शनिक भी थे। सुशांत को किताबें पढ़ना, साइंस और एस्ट्रोनॉमी में उन्हें काफी रुची थी। साइंस में रुचि होने के कारण वह अमेरिका में नासा और यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च लैब सर्न का भी दौरा कर चुके थे। इस लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत के बाद विजय देवरकोंडा को दूसरे स्थान पर जगह मिली है। वहीं आदित्य रॉय कपूर, विक्की कौशल, दुलकर सलमान, विराट कोहली, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, गुरफतेह सिंह पीरजादा और सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है।

एक्सीडेंट के बाद फिर से योगा करके खुश हैं टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी

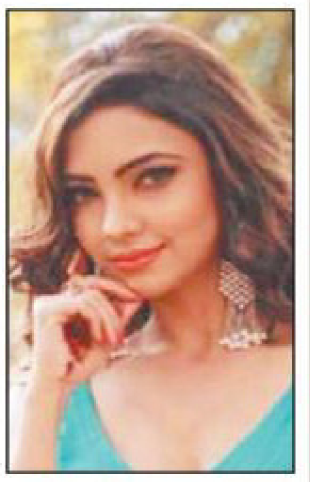

'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस पूजा बनर्जी ने बताया उन्होंने 2019 में एक बड़ी दुर्घटना से उबरने के बाद फिर से योग करना शुरू कर दिया है। पूजा ने हादसे को याद करते हुए कहा, '' मैं कुछ साल पहले एक रियलिटी शो के सेट पर हादसे का शिकार हो गई थी। इस घटना के कारण मेरी दोनों बाहों में कई फ्रैक्च र हो गए थे। जिसके बाद मुझे एक सर्जरी करानी पड़ी। डॉक्टर्स ने मेरे हाथों में दो रॉड और आठ पेंच लगाए।'' सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर खुलासा किया, ''सर्जरी के बाद, मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझे लगा कि मैं कभी भी सामान्य स्थिति में वापस नहीं आ पाऊंगी और अपने हाथों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। मैं चीजों को उठा या पकड़ नही पा रही थी। मैं कसरत नहीं कर सकती थी या बहुत सी चीजें जो मुझे पसंद थीं। वो समय बहुत डिफिकल था, लेकिन मैंने खुद को प्रेरित किया और धीरे धीरे लगातार काम करते करते मैं ठीक हो गई।'' पूजा ने आखिरकार योग फिर से शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि योगा शांति और ऊर्जा का स्रोत है। पूजा कहती हैं कि ठीक होने के बाद उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अपने शरीर में आत्मविश्वास विकसित किया है, जिसे मैंने दुर्घटना के बाद थोड़ा खो दिया था। यह निश्चित रूप से एक जबरदस्त यात्रा रही है, लेकिन यह कहने के बाद, मैं आभारी हूं, और मैं बस खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से जितना हो सके खुद को आगे बढ़ाऊंगी। वर्कफ्रंट की बात करें तो पूजा जी टीवी के लोकप्रिय डेली सोप 'कुमकुम भाग्य' में रिया का किरदार निभा रही हैं।

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने जन्मदिन पर मांगी दुआ

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर प्रशंसकों, फॉलोवरों, सहयोगियों और दोस्तों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद दिया। जन्मदिन 2 जून को था। सोनाक्षी ने बताया कि उन्होंने जन्मदिन पर ईश्वर से दुआ मांगी कि इस साल सामान्य जीवन बहाल हो, जैसा कि कोविड-19 महामारी से पहले था। उन्होंने लिखा, ''मेरी इच्छा है कि मेरे अगले जन्मदिन तक, चीजें फिर से सामान्य हो जाएं, जैसा हम सभी चाहते हैं। और उन लोगों के लिए एक मौन प्रार्थना, जो हमें छोड़ गए हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी मदद करें, जितना हम कर सकते हैं। मैंने आपइ सबकी खुशी, स्वास्थ्य और इस तबाही के अंत की कामना की। इसके अलावा, अब कोई और जन्मदिन लॉकडाउन में ना आए। आप सबने मुझे जो प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद।'' वर्कफ्रंट पर बात करें तो सोनाक्षी अजय देवगन के साथ 'भुज : द प्राइड ऑफ इंडिया' में दिखाई देंगी। फिल्म में संजय दत्त और नोरा फतेही भी हैं। इसके अलावा, अभिनेत्री 'फॉलन' के साथ अपनी वेब सीरीज की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, सीरीज में वह एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रही है।

थ्रिलर करना एक्टर्स के लिए फायदेमंद होता है

साउथ स्टार तमन्ना भाटिया को लगता है कि थ्रिलर में भूमिका चुनना हमेशा एक एक्टर के लिए एक फायदा हो सकता है क्योंकि यह जोनर बहुत अधिक पसंद किया जाता है। इस साल, तमन्ना ने अप्रैल में तेलुगु वेब सीरीज 'इलेवन्थ ऑवर' के साथ अपना डिजिटल डेब्यू किया, जो एक क्राइम थ्रिलर है। इसमें उनके साथ अदिथ अरुण और वामसी कृष्णा भी नजर आए थे। मई में, वह पसुपति, जीएम कुमार, अरुलदास और विवेक प्रसन्ना के साथ तमिल व्होडयूनिट ड्रामा 'नवंबर स्टोरी' के साथ फिर से ओटीटी स्पेस में नजर आईं। तमन्ना का कहना है कि एक थ्रिलर, अगर अच्छी तरह से किया जाता है, तो आपके पास बिंग वॉच देखने की क्षमता होती है। अब हर शो बनाने वाला चाहता है कि आप उसके शो को देखे, पसंद करें। इसलिए, जब आप थ्रिलर जैसी शैली चुनते हैं और अगर इसे अच्छी तरह से किया जाता है, तो यह काफी हिट हो सकता है। '11 वां घंटा' एएचए पर स्ट्रीम हो रही है जबकि 'नवंबर स्टोरी' डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर स्ट्रीम हो रही है।

अक्षय कुमार, चिरंजीवी ने फिक्की कोरोना जागरूकता अभियान का समर्थन किया

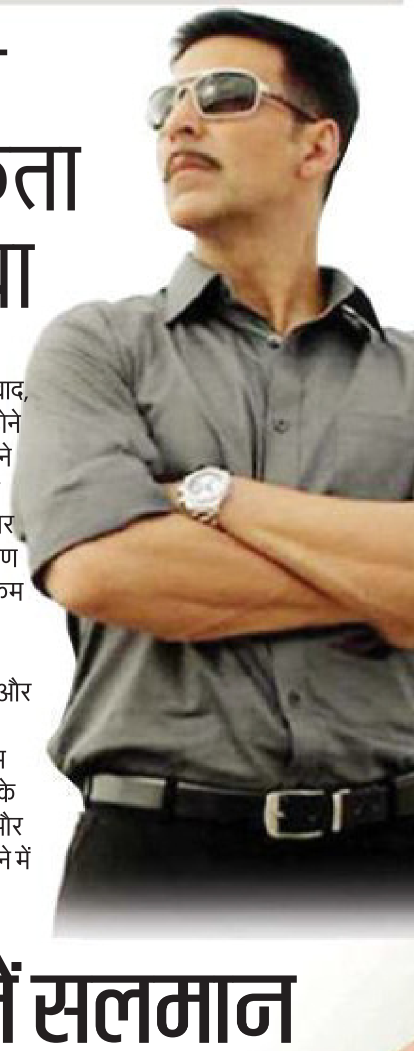

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार विभिन्न क्षेत्रों के फिल्म सितारों के साथ मिलकर कोविड के उचित व्यवहार, टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक सामाजिक अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है 'कोरोना को हराना है'। तेलुगु आइकन चिरंजीवी, तमिल स्टार आर्य और कन्नड़ स्टार पुनीत राजकुमार भी अभियान का हिस्सा हैं।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा यह अभियान पंजाबी, मराठी और हिंदी में शुरू किया जाएगा। फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा: ''हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के लिए धन्यवाद, हम एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां यह महसूस होने लगा है कि यह बदल रहा है। लेकिन हमें बने रहना चाहिए। खुद को, अपने परिवार और अपने समुदायों को वायरस के निरंतर प्रसार से बचाने के लिए सतर्क रहें। यह टीकाकरण को बढ़ाने और एक प्रभावी निवारक कार्यक्रम को लागू करने का समय है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हम भविष्य के लिए तैयार हैं और वायरस के प्रभाव को जीवन और आजीविका पर कम कर सकें।'' गुप्ता ने कहा, ''यह हम पर निर्भर करता है कि हम सभी भारतीयों को प्रभावी संचार रणनीति के माध्यम से विशिष्ट शिक्षा की जानकारी दें और सभी को कोविड-उपयुक्त व्यवहार अपनाने में सक्षम बनाएं।''

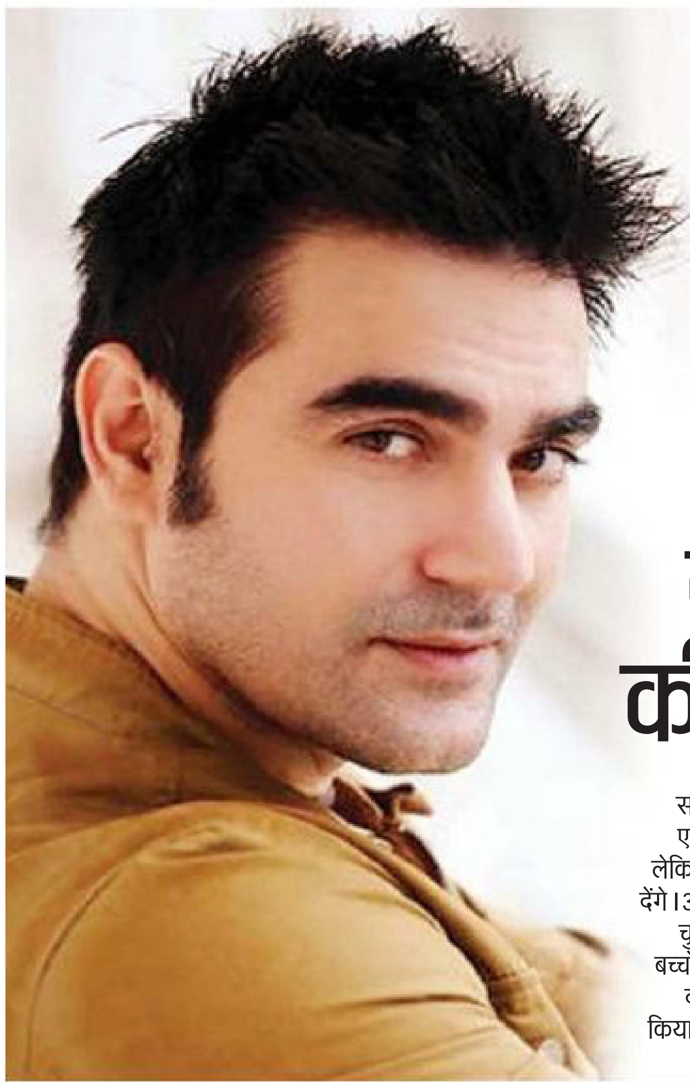

दबंग द एनिमेटेड सीरीज में सलमान की आवाज का इस्तेमाल नहीं हुआ

सलमान खान का इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे का कैरेक्टर 'दबंग द एनिमेटेड सीरीज' में एनिमेटेड अवतार में नजर आने वाला है। लेकिन सुपरस्टार शो में अपने लोकप्रिय किरदार को आवाज नहीं देंगे। अरबाज कहते हैं, ''चुलबुल पांडे को बनाने के पीछे का विचार चुलबुल का हर घर में फेमस होना है। साथ ही इस किरदार को बच्चों से जो बड़ी और सबसे विनम्र प्रशंसा मिलती है, इसने ही हमें दबंग पर आधारित एक एनिमेटेड सीरीज बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शो के बारे में बताया, ''दबंग द एनिमेटेड सीरीज'' दबंग का एक रूपांतरण और पुनर्कल्पना है। एक्शन कॉमेडी सीरीज पुलिस अधिकारी चुलबुल पांडे के दिन प्रतिदिन के जीवन का वर्णन करती है, जो शहर को सुरक्षित रखने के लिए बुराई का सामना करता है। इसमें उसका छोटा भाई मक्खी भी शामिल है। शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर प्रसारित होगा। एक अभिनेता के रूप में अपनी आगामी परियोजनाओं के बारे में, अरबाज ने कहा, ''मेरे पास अभी कुछ दिलचस्प परियोजनाएं हैं। जिसमें अप्लॉज एंटरटेनमेंट साथ एक अनटाइटल्ड सीरीज और दो फीचर फिल्म परियोजना 'रोजी', सुपरनेचुरल थ्रिलर और 'चकरी' जो एक दिलचस्प नाटक है, शामिल है''

पेरिस में यूनान की मारिया सकारी फ्रेंच ओपन टेनिस में खेलती हुईं।

लियोन से बेहतर हैं अश्विन : बट

करांची। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने भी ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर इयान चैपल के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें चैपल ने टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन को न्यूजीलैंड के स्पिनर नाथन लियोन से बेहतर बताया था। लियोन ने 100 टेस्ट में 399 विकेट अपने नाम किए हैं जबकि अश्विन ने 78 टेस्ट मैचों में ही 409 विकेट ले लिए हैं। वह 2010 में पदार्पण के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (सभी 3 प्रारूपों को मिलाकर) में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। बट ने कहा, मैं भी चैपल से सहमत हूं। यदि आप दोनों की तुलना करते हैं तो दोनों की गेंदबाजी में अच्छी लाइन और लैंथ है हालांकि जब विविधताओं की बात आती है तो अश्विन बेहतर नजर आते हैं। अगर आपको किसी एक को चुनना है और उनकी उपयोगिताओं को देखना है तो मैं अश्विन को चुनूंगा। वह बेहतर बल्लेबाजी करते हैं, तीनों प्रारूपों में खेलते हैं और हमेशा अच्छा करते हैं। बट ने कहा, यहां तक कि उनके एक्शन को चुनना थोड़ा मुश्किल है जबकि नाथन लियोन का एक्शन बेसिक है। मैं यह नहीं कहूंगा कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है लेकिन मेरी तरफ से अश्विन के पास बढ़त है। अश्विन कोण और क्रीज का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं और अजंता मेंडिस की तरह अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं। वह खेल के तीनों प्रारूपों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। अश्विन ने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और तभी दिखा कि लियोन और अश्विन में काफी अंतर है। बट ने कहा, मुझे चैपल से सहमत होना होगा। लियोन भी एक शानदार गेंदबाज है। लेकिन अगर आप दोनों की तुलना करते हैं और अगर मैं कप्तान होता तो मैं अश्विन को चुनता। वह बल्लेबाजी भी करता है। अश्विन हाल ही में भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर के उस बयान के बाद चर्चा आए जब मांजरेकर ने कहा कहा था कि वह अश्विन को सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक नहीं मानते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया , दक्षिण अपफ्रीका और इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

भारत की सुशीला ने ओलंपिक क्वालीफाई किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत की जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी ने अस्थाई रूप से टोक्यो ओलिम्पिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। सुशीला के टोक्यो ओलिम्पिक में हिस्सा लेने की पुष्टि 28 जून को क्वालीफाई करने वाले खिलाडिों की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही होगी। अभी उन्हें महाद्वीपीय कोटा के आधार पर अस्थाई रुप से प्रवेश मिला है। इसके साथ ही सुशीला विश्व जूडो चैंपियनशिप के 48 किग्रा वर्ग के पहले दौर में ही हार गयीं थीं। इस प्रकार उनके अभी 989 अंक हैं जिससे वह एशियाई सूची में 7वें स्थान पर ही पहुंची हैं। अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ की वेबसाइट के अनुसार, अब तक जारी की गई सूचना अस्थाई है और सिर्फ उन जुडोकाओं के नाम दिए गए हैं जो अगर आज ओलिम्पिक होते तो क्वालीफाई कर जाते। महाद्वीपीय कोटा क्षेत्र में जूडो खिलाड़ी की रैंकिंग के आधार पर दिए जाते हैं। इसमें एशिया के पास 10 कोटा स्थान हैं। इस सूची में ओलिम्पिक क्वालीफिकेशन अंक हासिल करने की अंतिम तिथि 28 जून 2021 तक काफी बदलाव होने की संभावना है। वहीं खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने सुशीला को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। रीजीजू ने ट्वीट किया कि मैं जुडोका सुशीला देवी को महिला 48 किग्रा वर्ग में महाद्वीपीय कोटा के जरिए टोक्यो 2020 के लिए क्वालीफाई करने पर बधाई देता हूं। भारत को गौरवांवित करके लिए हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जूडो महासंघ ने हालांकि कहा कि वह अंतिम सूची का इंतजार करेगा।

दूसरे टेस्ट मैच में खेल सकते हैं बोल्ट

लंदन, (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में खेल सकते हैं। ऐसा इंग्लैंड में नए क्वारंटीन प्रोटोकॉल के चलते संभव हुआ है। बोल्ट पिछले सप्ताहांत इंग्लैंड में अपनी टीम में शामिल हुए थे और क्वारंटीन नियमों में मिली राहत के साथ वह सीधे प्रशिक्षण शुरू करने में कामयाब रहे थे और अब साउथम्प्टन में डब्ल्यूटीसी फाइनल में भारत का सामना करने से पहले उनके पास इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अभ्यास करने का भी अवसर है। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टेड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के ड्रॉ के साथ समाप्त होने के बाद कहा कि बोल्ट के पास एक अवसर है। कुछ चीजें बदल गई हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपनी क्वारंटीन शर्तों में ढील दी है, इसलिए बोल्ट तय समय से तीन या चार दिन पहले ही क्वारंटीन से बाहर आ गए हैं। पहले हमारे पास जो भी जानकारी थी उस हिसाब से हमारी योजना बोल्ट को दूसरे टेस्ट में शामिल नहीं करने की थी पर अब उनके तीन दिन पहले क्वारंटीन से बाहर आने से शायद पह दूसरा टेस्ट खेल सकते हैं।

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में प्रभावी रहे थे। अब अगर बोल्ट को खेलने का अवसर मिलता है तो कीवी टीम का गेंदबाजी आक्रमण और बेहतर हो जाएगा। बोल्ट के आने के कारण एजबेस्टन टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड प्रबंधन के लिए टीम चयन कठिन होगा। कीवी कोच स्टीड ने कहा कि हमने अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया है और हम बोल्ट को दूसरे टेस्ट में खेलाते हैं या नहीं , यह तय करने से पहले हम उन्हें 48 घंटे पहले जानकारी देंगे।

इटली में एफआईवीबी नेशनल वॉलीबाल लीग में खेलते हुए सर्बिया के जोवाना कोसिस।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय ने रॉबिन्सन के निलंबन को गलत बताया

लंदन, (एजेंसी)। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन के निलंबन का मामला बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी आठ साल पुराने विवादित ट्वीटस को लेकर दी गयी निलंबन की सजा को ज्यादा ही कड़ा बताया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यालय (पीएमओ) के प्रवक्ता ओलिवर डोडेन ने अपने ट्वीट में लिखा, रॉबिन्सन के ट्वीट आपत्तिजनक और गलत थे पर यह पुरानी बात है और उसने यह सबा बातें जब लिखीं थीं तब वह किशोरावस्था में थ। अब इस मामले में रॉबिन्सन ने माफी भी मांग ली है। इसके बाद भी ईसीबी ने उसे निलंबित करने का गलत फैसला लिया है जिसपर उसे फिर से विचार करना चाहिये।

गौरतलब है कि रॉबिन्सन ने 18 और 19 साल की उम्र में कई ट्वीट किए थे जिनको लेकर उन्हें अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये ट्वीट नस्लवाद और लिंगभेद से जुड़े थे। मैच के दौरान यह ट्वीट वॉयरल हो गये थे जिसके लिए रॉबिन्सन ने माफी भी मांगी थी। ईसीबी ने ससेक्स के इस गेंदबाज के बारे में कहा, रॉबिन्सन तुंरत ही इंग्लैंड की टीम को छोड़कर अपनी काउंटी में वापसी करेंगे।

वहीं इससे पहले इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने साल 2012-13 में किए गए नस्लीय ट्वीट की जांच लंबित रहने तक रॉबिन्सन को से निलंबित कर दिया गया

था। इस फैसले पर टीम के कप्तान जो रुट ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि वह इस मामले में रॉबिंसन के साथ हैं। रॉबिन्सन ने लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए सीरीज के पहले मैच में डेब्यू करने के कारण ही गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था।

पूर्व स्ट्राइकर बोला, भारतीय हॉकी टीम के पास टोक्यो ओलंपिक जीतने का अच्छा अवसर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व स्ट्राइकर तुषार खांडेकर का मानना है कि भारतीय हॉकी टीम इस बार टोक्यो ओलंपिक में पदक की प्रबल दावेदार है। तुषार के अनुपार पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। टीम को विश्व की शीर्ष स्तर की टीमों के खिलाफ किये अच्छे प्रदर्शन से आत्मविश्वास मिला है जो कि ओलंपिक में जीत के लिए सबसे जरुरी है। खांडेकर ने कहा कि मुझे लगता है कि अभी टीम जैसा प्रदर्शन कर रही है उसे देखते हुए वे पदक के प्रबल दावेदार बन जाते हैं।

उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी जानता है कि ओलिम्पिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में छोटी गलतियां कितनी नुकसान देह हो सकती है, इसलिए सभी अपने और से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास करेंगे। भारतीय टीम ने पिछले महीनों में अर्जेंटीना और यूरोप के अपने दौरों में अच्छा प्रदर्शन किया था। खांडेकर ने कहा कि हमने प्रत्येक ओलंपिक खेल से सबक लिया है। हम 2008 में क्वालीफाई नहीं कर पाए पर लंदन में 12वें और रियो में आठवें स्थान पर रहे। हमने 2012 में जो गलतियां की थी उन्हें भी 2016 रियो ओलंपिक में दूर किया था।

उन्होंने कहा कि लंदन ओलिम्पिक में भाग लेने वाले खिलाडिों जैसे श्रीजेश, मनप्रीत, सुनील, दानिश मुज्तबा, रघुनाथ और रियो में खेले खिलाड़ियों ने तय किया कि टीम लंदन वाली गलतियों को नहीं दोहराएगी। खांडेकर ने कहा कि इसी तरह से मुझे विश्वास है कि रियो ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ी इस टीम को उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिससे वे टोक्यो में इन्हें न दोहराते हुए बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत दर्ज कर

विलियमसन को साउथम्पटन में कम घास वाली पिच मिलने की उम्मीद

लंदन, (एजेंसी)। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने कहा है कि 18 जून से साउथम्पटन में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में साउथम्पटन की पिच पर कम घास होने की उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा, थोड़ी घास कट सकती है और उस पर रोलर चलाया जा सकता है।

मैं अभी टीम के बारे में अधिक नहीं जानता। देखते हैं कि हालात कैसे होते हैं। हमने अभी तक प्रत्येक दिन बारिश देखी है। साथ ही कहा कि अलग-अलग हालातों में ड्यूक गेंदों का सामना करने का अनुभव हासिल करना अच्छा रहेगा। वहीं इस मैच के लिए न्यूजीलैंड की मुख्य चिंता नंबर सात पर बल्लेबाज या ऑलराउंडर को लेकर है विलियमसन ने कहा कि उनके पास सभी विकल्प खुले हैं।

उन्होंने कहा, हमें इस तरह के फैसले करने के लिए परिस्थितियों का आंकलन करना होगा। हम जब भी अलग स्थान पर खेलते हैं परिस्थितियों के अनुसार टीम का चयन करते हैं जो हमारे अनुकूल हो। विलियमसन ने कहा कि तेज गेंदबाज नील वैगनर भारत के खिलाफ अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, उसकी लंबे स्पैल करने और लंबे समय तक दबाव बनाए रखने की क्षमता ऐसी है, जिसके कारण वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना सफल रहा है। वह हमारी टीम का अहम सदस्य है। उनका टीम में होना शानदार रहेगा। विलियमसन से कहा कि विराट कोहली के खिलाफ उन्होंने विभिन्न स्तरों और प्रतियोगिताओं में एक दूसरे के खिलाफ खेला है और दोनो ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैदान पर साथ में उतरना, टॉस करना और पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में एक दूसरे से मिलना काफी अच्छा अहसास रहेगा।

विलियमसन ने कहा कि वह भारतीय गेंदबाजी की मजबूती और हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उनकी ऐतिहासिक जीत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने कहा, हां , उनके पास शानदार आक्रमण है. वह निश्चित तौर पर एक बेहतरीन टीम है। हमने उनकी मजबूती को देखा है। साथ ही कहा कि भारतीय टीम के पास शानदार स्पिन आक्रमण के साथ ही अच्छे तेज गेंदबाज भी हैं जिससे फाइनल मुकाबला रोमांचक होगा।

धोनी की कप्तानी में सीएसके से खेलना चाहते हैं राशिद

अबुधाबी, (एजेंसी)। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान का सपना है कि वह भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में आईपीएल खेलें। उन्होंने कहा, मेरा एक सपना है कि मैं धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) की ओर से खेलूं। उनकी कप्तानी में खेलने के अनुभव से मुझे काफी लाभ मिलेगा। राशिद ने कहा कि किसी भी गेंदबाज के लिए विकेटकीपर की भूमिका काफी अहम होती है और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में धोनी से बेहतर कोई नहीं है। राशिद ने कहा कि धोनी ने हाल ही में उन्हें काफी अहम सलाह दी थी।

उन्होंने कहा, धोनी ने मुझसे कहा था कि क्षेत्ररक्षण के समय डाइव लगाने और गैर जरूरी थ्रो को लेकर मुझे सजग रहने की जरूरत है। वहीं राशिद सीमित ओवरों में भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा के बल्लेबाजी से भी काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, मैं यह मानूंगा कि उनके पास अतिरिक्त समय होता है। मैंने काफी कम ऐसे खिलाड़ियों को देखा है जिनके पास शॉट लगाने के लिए इतना समय होता है। वह 145-150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करने वालों पर भी ऐसे शॉट लगाते हैं जैसे 120 किलोमीटर की रफ्तार से कोई गेंदबाजी कर रहा हो। इसके साथ ही राशिद ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की बल्लेबाजी में सफलता के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि विराट कभी भी अपना ध्यान भंग नहीं होने देते हैं। इसके कारण ही उनकी लय बनी रहती है।

भारतीय महिला तीरंदाजी पेरिस में पृथकवास से गुजर रहीं

पेरिस, (एजेंसी)।भारतीय महिला तीरंदाजी टीम 20 जून से अपनी अंतिम ओलिम्पिक क्वालीफिकेशन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गयी है। भारतीय महिला तीरंदाज अभी 10 दिन के अनिवार्य पृथकवास से गुजर रही हैं। ओलंपिक क्वालीफायर के कारण वे पुरुष टीम से पहले यहां पहुंचीं हैं। पूर्व नंबर एक तीरंदाज दीपिका कुमारी के साथ ही इस दल में अंकिता भकत और कोमोलिका बारी शामिल हैं।

साक्षी ने फार्म हाउस का वीडियो जारी किया , लोग बोले माही भाई को दिखाइए

रांची। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी आजकल अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान हैं। इस बार उनकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था पर कोरोना संक्रमण के कारण आईपीएल निलंबित हो गया था। तभी से धोनी धोनी रांची स्थित अपने फार्म हाउस में ही रह रहे हैं। धोनी की पत्नी साक्षी ने धोनी के खूबसूरत फार्म हाउस की एक तस्वीर भी साझा की है। इसमें साक्षी ने वीडियो के जरिए फार्म हाउस को दिखाया है। साक्षी ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोमवार को शेयर किया। लोग कमेंट्स में फार्म हाउस की तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग धोनी को देखना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, प्लीज माही भाई को दिखाइए. धोनी के इस फार्म हाउस में स्वीमिंग पूल से लेकर इंडोर स्टेडियम और जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। टीम इंडिया के लगभग सभी क्रिकेटर इस फार्म हाउस में आये हैं। धोनी के फार्म हाउस के लॉन में उनके पसंदीदा पालतू जानवर दिखाई देते हैं। धोनी यहीं पर अपने इन पेट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। उन्होंने कई बार अपने डॉग्स को ट्रेनिंग देते हुए के वीडियो भी साझा किए हैं। इस फार्म हाउस में हर तरफ हरियाली ही नजर आती है। फार्म हाउस में अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधे लगे हैं। धोनी के इस फार्म हाउस में पार्किंग भी हैं, जहां उनकी पसंद की गाड़ी और बाइकों का कलेक्शन रहता है। फार्म हाउस में एक आलिशान बंग्ला भी है यह 7 सात एकड़ में फैला हुआ है।

जर्मनी में लाटीविया के गोलकीपर रॉबर्टो ओजॉल फुटबॉल मैच में गोल रोकने में नाकाम रहे।

विराट को आउट करना है सकारिया का सपना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आईपीएल के निलंबित हुए सत्र में अपने शानदार खेल से सभी का ध्यान खींचने वाले राजस्थान रॉयल्स के बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने कहा है कि उनका सपना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर (आरसीबी) के कप्तान विराट कोहली को आउट करना है।

सकारिया ने कहा कि अगर मैं विराट को आउट करता हूं तो वह मेरा आइडियल विकेट होगा। उन्होंने कहा विराट इस समय दुनिया के महान बल्लेबाज हैं। वे विकेट आसानी से नहीं देते। वे ओवर में एक-दो रन बनाकर चौका मार ही देते हैं। ऐसे में वो ओवर में 10 रन बना लेते हैं। वहीं अन्य बल्लेबाज बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते हैं।

सकारिया ने खुलासा किया कि आरसीबी ने यह भी कहा कि नीलामी में आरसीबी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की और वे स्वयं भी विराट की टीम से खेलना चाहते थे पर राजस्थान रॉयल्स ने 1.20 करोड़ रुपए की बोली लगाकर चेतन को अपनी टीम में शामिल कर लिया जबकि आरसीबी ने उनपर 1.10 करोड़ तक की ही बोली लगाई थी। चेतन ने इस बारे में कहा कि आरसीबी ने मुझे खरीदने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान की टीम अंत में सफल रही।

सकारिया ने कहा कि मैं आरसीबी की टीम में जाना चाहता था, क्योंकि मैं उस टीम के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ था पर अंत में क्रिकेट मायने रखता है। आपको क्रिकेट खेलनी है, चाहे वह किसी भी टीम से खेलो। चेतन आईपीएल 2020 में आरसीबी के नेट बॉलर रहें हैं। उन्होंने बताया कि जब वे आरसीबी के नेट बॉलर थे तो उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और विराट ने भी उनके साथ अपना कुछ अनुभवों को साझा किया।

सकारिया ने कहा, मैं हर बाएं हाथ के गेंदबाज को फॉलो करता हूं। मुझे बाएं हाथ के गेंदबाज काफी पसंद हैं। जैसे जहीर खान, वसीम अकरम और ट्रेंट बोल्ट। मैं हर गेंदबाज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उनकी चीजों को अपनी गेंदबाजी में लागू करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि वो मेरे एक्शन के साथ फिट होती है या नहीं।